04/2013

सप्रू हाउस लेख

दक्षिण - दक्षिण संबंधों में नये सीमांत

भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देशों के बीच संबंध

सारंग शिडोर

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई दिल्ली-110001

दक्षिण - दक्षिण संबंधों में नये सीमांत

भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देशों के बीच संबंध

सारंग शिडोर

दक्षिण - दक्षिण संबंधों में नये सीमांत

भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देशों के बीच संबंध

प्रथम प्रकाशन, 2013

कॉँपीराइट © अंतर्राष्ट्रीय मामलों की
भारतीय परिषद ISBN : 978-93-83445-
00-4

सभी अधिकार संरक्षित हैं। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को कॉँपीराइट मालिक से अनुमति के बगैर पुनरुत्पादित, पुनःप्राप्ति प्रणाली में भंडारित, अथवा किसी भी प्ररूप में चाहे इलैक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोकॉँपी से रिकार्डिंग अथवा अन्यथा, रूपांतरित नही किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में व्यक्त किये गये तथ्य एवं मतों की जिम्मेदारी पूर्णतया लेखक के पास सुरक्षित है तथा उसका विवेचन आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के विचारों को व्यक्त नहीं करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की
भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़,
नई दिल्ली- 110 001,
भारत
Tel. : +91-11-23317242, Fax: +91-11-23322710
www.icwa.in

के द्वारा प्रकाशित
अल्फा ग्राफिक्स
6A/1, गंगा चैम्बर्स, डब्ल्यू.
ई. ए., करोल बाग, नई
दिल्ली-110005 Tel. :
9312430311
ई-मेल : tarunberi2000@gmail.com

विषयवस्तु

परिचय	5
सक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	6
व्यापार एवं निवेश	10
सर्वसमावेशी रुझान	10
राज्य-दर-राज्य एवं निजी क्षेत्र पहलें	14
मुख्य क्षेत्र	16
निष्कर्ष	24
राजनीतिक एवं रणनीतिक संबंध	26
द्विपक्षीय संबंध	27
क्षेत्रीय संपर्क	33
रक्षा एवं अंतरिक्ष	34
निष्कर्ष	37
वैश्विक शासन	38

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सुधार 39

दक्षिण-दक्षिण संस्थान निर्माण 40

जलवायु परिवर्तन 41

आतंकवाद और परमाणु हथियार 42

संप्रभुता और मानवीय हस्तक्षेप 43

सांस्कृतिक और व्यक्ति-दर-व्यक्ति संबंध 44

आगे का मार्ग 48

समाप्ति टिप्पणी 50

स्वीकृतियां 61

दक्षिण - दक्षिण संबंधों में नये सीमांत
भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देशों के बीच संबंध

परिचय

1960 तथा 1970 की धीमी विकास-दर के तीस साल बाद भारत की विकास-दर इस स्तर पर पहुँच गई जहां भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वहां पहुँच गया जहां पूर्व में दूर-दराज के क्षेत्र और राज्य, देश के भविष्य के विकास के लिए प्रमुख हो रहे हैं। भारत की आर्थिक उन्नति का सहगामी स्थिति व्यावहारिक रूप से विश्व के हर भाग के साथ राजनीतिक वृद्धि के रूप में भी सामने आई है। इस प्रक्रिया ने पश्चिम में वित्तीय संकट, सापेक्ष अमेरिकी गिरावट की धारणा और दक्षिण-दक्षिण संबंधों को गहरा करने के साथ अधिक से अधिक विशेषता हासिल कर ली है।

इस सूची में शामिल होने वाले नवीनतम और अनंतिम देश

लैटिन अमेरिका और कैरेबिया (एलएसी) है। क्षेत्र में महत्वपूर्ण देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध 2000 में तेजी से बढ़े और अब 35 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहे हैं। इसी के समानांतर शीत युद्ध की समाप्ति ने लैटिन अमेरिका को महाशक्तियों के हस्तक्षेपों और सैन्य तानाशाहियों से उभरने का अवसर दिया। प्रजातंत्र के गहराने से आर्थिक आधारभूत बातों , क्षेत्रीय एकीकरण और एक गति से समान विकास , तथाकथित 'ब्रासीलिया कंन्सेन्शस' के रूप में उभरकर सामने आया।

प्रारंभ में पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लगभग पूर्ण नेतृत्व में, भारत तथा लैटिन अमेरिका के संबंधों ने हाल ही में गहरी देश-दर-देश एवं व्यक्ति-से-व्यक्ति का रूप लेना शुरू कर दिया है। भारत और लैटिन अमेरिका ने बहुस्तरीय स्तरों पर दोनों प्रकार से ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) जैसे वैश्विक दक्षिण के नये संगठन के तौर पर तथा साथ ही साथ जी20 जैसे वैश्विक शासन के संस्थान के तौर पर व्यवसाय प्रारंभ कर दिए हैं। इन कार्यों को हाल ही में वैश्विक शासन और सतत और न्यायसंगत विकास के क्षेत्रों में काफी गहन से बातचीत के साथ सीमित किया गया है।

यह लेख एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों के रुझानों को विशेषरूप से वर्ष 2000 की समयावधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्लेषित करता है। राष्ट्र और गैर-राष्ट्र दोनों अभिनेताओं की भूमिकाओं को संबंधित क्षेत्रीय संस्थानों के साथ-साथ समाधान किया जाएगा। अधिक सैद्धांतिक रूप से उन्मुख निष्कर्ष अनुभाग आगे के रास्ते को प्रकाशित करने का प्रयास करता है। इस लेख का उद्देश्य भारत में उन नीति निर्माताओं के लिए है , जो संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं के रुझानों पर कब्जा करना चाहते हैं, साथ ही लैटिन अमेरिका में जो एशिया में अपने तेजी से उभरते साथी के साथ खुद को परिचित करना चाहते हैं उन पर भी केंद्रित है।

संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत और एलएसी के मध्य भौगोलिक दूरी और आम इतिहास की कमी ने इतिहास के माध्यम से एक दूसरे की न्यूनतम जागरुकता की ओर अग्रेषित किया है। एलएसी पर भारत का पहला महत्वपूर्ण प्रभाव 19वीं सदी के मध्य में था जब ब्रिटिशों के द्वारा हजारों करारबद्ध भारतीय मजदूर कैरेबिया में लाए गए

थे। इस कार्य ने वर्तमान में उस क्षेत्र में स्थायी अप्रवास की स्थापना की।

स्वतंत्रता के लिए 20वीं सदी में भारत के पहले संघर्ष नें लैटिन अमेरिका की पहली आधुनिक जागरुकता देखी। प्रजातंत्रवादी विद्रोही मानबेन्द्र नाथ राय संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यावर्तन पर मेक्सिको भाग गये और 1917 में मैक्सिकों की सांप्रदायिक पार्टी की स्थापना की। यह एक भारतीय के द्वारा बहुत दूर और अपरिचित देश की राजनीति में उनके द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण योगदान था।

जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में अमेरिका के प्राचीन और औपनिवेशिक इतिहास का अध्ययन किया और वे सिमन बोलीवर और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए किये गये उनके संघर्ष के बहुत बड़े समर्थक थे। अमेरिका के 20 वीं सदी के क्षेत्र के शाही वर्चस्व की नींव के रूप में मोनरो सिद्धांत को देखते हुए उन्होंने लैटिन अमेरिकी मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका को भी नकारात्मक माना था। लैटिन अमेरिकी नेताओं तथा स्वतंत्र भारत के होने वाले नेताओं की पहली मुलाकात 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस

अगेन्स्ट इंपीरियलिज्म में हुई थी। नेहरू को दो तरफा आम विकास चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

स्वतंत्रता से पहले की अवधि के दौरान अर्जेन्टीना अब तक इस क्षेत्र में भारत के लिए का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था यह एक वाणिज्यिक संबंध था जो 19 वीं शताब्दी में दोनों देशों में विदेशी निवेश के ब्रिटिश वर्चस्व के कारण सामने आया था। द्वितीय विश्व युद्ध, 1946 में भयंकर अकाल की संभावना के साथ भारत में बहुत अधिक भोजन की कमी को लाया। भारत की एक अपील के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अर्जेन्टीना और ब्राजील ने इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान मकई और गेहूं के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारतीय स्वतंत्रता ने भारत-एलएसी संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की , जिसमें भारत ने 1948 में ब्राजील से प्रारंभ करते हुए कई देशों में अपने स्वयं के दूतावासों की स्थापना की। इसके स्थायी मिशनों की स्थापना अर्जेन्टीना में (1949), चिली में (1957), मैक्सिकों में (1960), क्यूबा में (1962), पेरू में (1968), कोलोम्बिया में (1970) तथा वेनेचुएला में (1972) में की थी। इनमें से कई देशों में , आधिकारिक संबंध भौतिक

रूप से भारतीय दूतावासों की स्थापना के पहले से ही प्रारंभ हो गए थे। यहां तक कि कई एलएसी देशों ने अपने प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना दिल्ली में पहले ही कर दी थी उदाहरणार्थ ब्राजी एवं चिली नें 1949, अर्जेन्टीना नें 1950 में, वेनेजुएला, पेरू, एक्वाडोर, बोलीविया और पनामा नें 1953 में और कोलम्बिया ने 1959।

स्वतंत्रता के बाद की तिमाही में एलएसी में भारतीय नेताओं द्वारा की गई दो यात्राएं महत्वपूर्ण है- पहली जवाहरलाल नेहरू की 1961 में की गई मैक्सिको की यात्रा और दूसरी विशेष रूप से 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा लैटिन अमेरिका की मौलिक बहु-देशीय यात्रा है जिसके दौरान उन्होंने ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना का दौरा किया था। एलएसी देशों के साथ भारत का छिट-पुट संपर्क 1970 और 1980 के दौर में भी जारी रहा और जिस दौरान राजीव गांधी के द्वारा 1985 में क्यूबा और 1986 में मैक्सिको की यात्राए शामिल थी। इस समयावधि के दौरान भारतीयों की तुलना में तुलनात्मकरूप से एलएसी देशों के प्रमुखों की यात्राएं अधिक रहीं जो की संभवतया क्षेत्रीय मुद्दों और प्रमुख शक्तियों के साथ भारतीय नेताओं के पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

इन यात्राओं के दौरान केंद्र में रहे द्विपक्षीय विचार-विमर्शों ने भारत और एलएसी की उस समय की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया जिनमें- संप्रभुता का सख्ती से पालन, परमाणु हथियारों का पुरजोर विरोध और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन, अमीर और विकासशील देशों के बीच असमानता को कम करने पर जोर, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों का समर्थन, उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव का विरोध करना शामिल था।

हालांकि, जब विशिष्ट भारतीय राजनीतिक हितों की बात आई, तो शीत युद्ध के समय में एलएसी की स्थितियां अक्सर दूरस्थ या विरोधात्मक थीं। इस तथ्य ने प्रतिबिंबित किया कि कुछ अपवादों के साथ, एलएसी देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दृढ़ता से संबद्ध किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद को उनके क्षेत्र और शासनों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया था, जबकि भारत ने सामान्य रूप से उपनिवेशवाद विरोधी और गुटनिरपेक्ष स्थिति को अपनाया था। उदाहरण के लिए जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और बाद में गोवा के पुर्तगाली उपनिवेशों के विलय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में

निर्णायक बहस ने एलएसी सदस्य देशों को प्रत्येक मामले में भारतीय कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए और पश्चिमी देशों द्वारा भारत के खिलाफ मतदान करते हुए पाया गया। 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के विषय में यूएनएससी की बहस के दौरान एक समान प्रवृत्ति देखी गई थी।

हालाँकि, ये एलएसी देश, कम से कम बनावटीतौर पर ही सही, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद जैसी वैश्विक समस्याओं अथवा 'न्यू इंटरनेशनल इकोनामिक आर्डर' के प्रतिमान के तहत तीसरी दुनिया के आर्थिक विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान एलएसी ने भारत का समर्थन किया था, जो संभवतः उस संघर्ष में वाशिंगटन के भारतीय-समर्थक रुख से प्रेरित था। इन रुझानों का एक बड़ा अपवाद फिदेल कास्त्रो के तहत 1962 के बाद का क्यूबा था, जो आम तौर पर भारत की स्थिति के साथ, विशेष रूप से तीसरी दुनिया की एकजुटता के मुद्दों पर परिवर्तित होता था।

शीत युद्ध के दौरान भारत और एलएसी के बीच राजनीतिक गतिशीलता अनिवार्य रूप से सीमित रही , क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण आर्थिक पूरक की कमी थी। इस अवधि के

दौरान व्यापार और निवेश संबंध दोनों के बीच आयात और निर्यात एक दूसरे के व्यापार क्षमता के 1 प्रतिशत से कम को दर्शाते थे। अलग-अलग स्तरों में भारत और एलएसी दोनों द्वारा अपनाई गई आयात प्रतिस्थापन की नीतियां इस आर्थिक भागीदारी की कमी की एक बहुत बड़ी कारक थी लेकिन न्यूनतम परिवहन संपर्क और सांस्कृतिक दूरी भी इसका महत्वपूर्ण कारक थे। 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति और भारत में आर्थिक उदारीकरण की पहल के कारण अमेरिकी सुरक्षा छाया को हटाने तक दोनों के बीच एक बड़ी पहल का इंतजार करना पड़ा। अगले भाग में हम वर्ष 2000 से भारत और एलएसी के बीच व्यापार और निवेश संबंधों का पर्यवेक्षण करेंगे।

व्यापार और निवेश

समग्र रुझान

व्यापार और निवेश पिछले एक दशक में भारत और लैटिन अमेरिका के बीच बातचीत का प्रमुख भाग रहा है। (चित्र 1) में दिया गया विवरण 1990 में भारत और लैटिन अमेरिका के मध्य बहुत कम 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर का

व्यापार था जो 1997 में 1 बिलियन के अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और फिर 2006 तक इसके पाँच गुना 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। H हालांकि इसमें अत्यधिक वास्तविक उछाल लगभग पिछले छः वर्षों में आया है जिसमें 2012 तक कुल व्यापार 32.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गया जिसने कि इसमें आयी लगभग 35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाया। हालांकि व्यापार संतुलन लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इस समय एलएसी के पक्ष में है।

ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑकड़े है और दर्शाते हैं कि दोनो के बीच आर्थिक संबंध ऊची उड़ान लेने की स्थिति में हैं। फिर भी आकंडों को इस संदर्भ में समाहित करना होगा। एलएसी भारत के कुल व्यापार का अभी भी मात्र 4 प्रतिशत (2001 में 2 प्रतिशत से) का प्रतिनिधित्व करता है। एलएसी के दृष्टिकोण से भारत के साथ व्यापार का कारक हालांकि बहुत छोटा है, जो इसके निबल व्यापार के मात्र 1 प्रतिशत (चीन के 8 प्रतिशत के साथ तुलना में) को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि यहां पर व्यापार परिमाणों में भविष्य के लिए असीम अवसर मौजूद हैं।

चित्र 1 : भारत-एलएसी व्यापार ने 2002 से पकड़ी

रफ्तार।

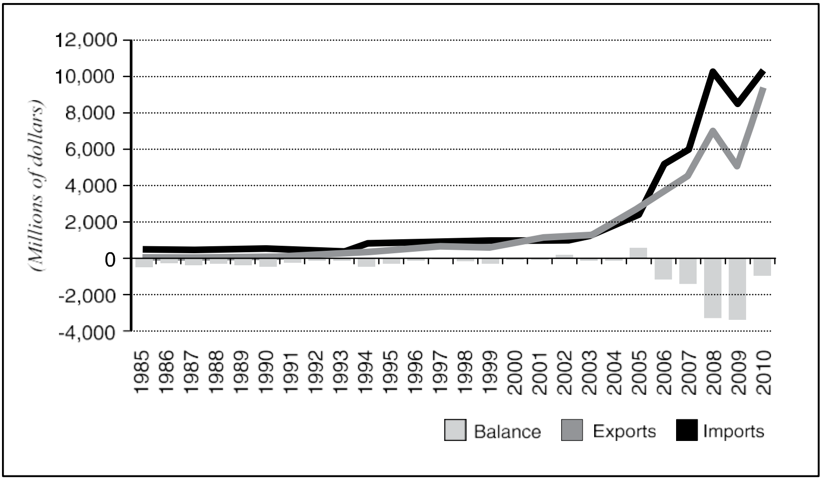

स्रोत **-यूएन ईसीएलएसी**

क्षेत्रीय तौर पर , एलएसी भारत को प्राकृतिक संसाधन एवं मुख्य उत्पाद जैसे कि कच्चा तेल और जैविक ईंधन, कॉपर एंव अन्य खनिज, चीनी, वानस्पतिक तेल और सोया की आपूर्ति करता है जबकि भारत परिष्कृत तेल उत्पादों, कपड़ो और धागों, अभियांत्रिकी से संबंधित सामान (ऑटो पार्टस के साथ), दवा उत्पादों एवं औषधियों की आपूर्ति करता है। भारत, देश में मौजूद अपनी शीर्ष आईटी कंपनियों जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एलएसी को आईटी एवं आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) का आपूर्तिकर्ता रहा है।

भारत-एलएसी व्यापार की ये दो अलग-अलग विशेषताएं उल्लेखनीय हैं पहली , यह उत्पादों की एक सीमित श्रेणी (विशेषकर एलएसी से आयात के मामले में) पर अत्यधिक केंद्रित है तथा दूसरी यह अंतर-उद्योग के बजाय अंतः-उद्योग है। यह लेख इन टिप्पणियों के महत्व पर फिर से विचार करेगा।

पेरू, एक्वाडोर और पनामा जैसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के साथ भौगोलिक रूप से भारत के मुख्य व्यापार साझेदार ब्राजील, वेनेजुएला, मैक्सिको, चिली, अर्जेन्टीन और कोलम्बिया है। उपरोक्त वर्णित नौ देश भारत-एलएसी व्यापार का 80 प्रतिशत

से भी अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। इसीलिए भौगोलिक रूप से भारत-एलएसी व्यापार को अधिकतर कम देशों (चित्र 2) पर केंद्रित होते देखा जा सकता है जो वर्तमान में नगण्य बातचीत वाले कई देशों में विस्तार के अवसरों की ओर संकेत करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर आकड़े भी कुछ इसी तरह की कहानी बताते हैं। एलएसी में भारत का निवेश प्राकृतिक संसाधनों, औषधियों और आईटी/आईटीईएस पर केंद्रित रहा है।

हाल ही में भारत ने इक्विटी तेल और गैस में बहुत अधिक निवेश किया है , विशेष रूप से ब्राजील और कोलंबिया में, जिससे वर्तमान में इस क्षेत्र में भारतीय निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र ऊर्जा बन गया है।

चित्र 2: क्षेत्र में कई छोटे देशों में केंद्रित, भारत-एलएसी व्यापार।

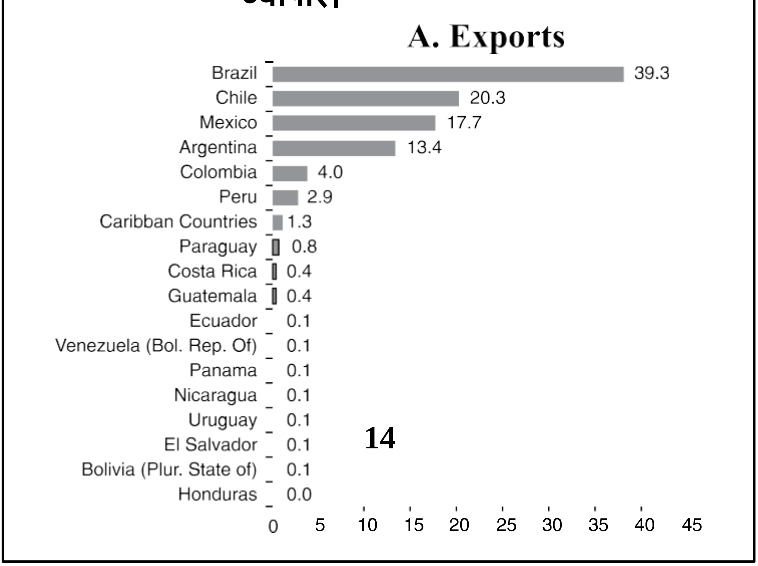

स्रोतः यूएन-ईसीएलएसी

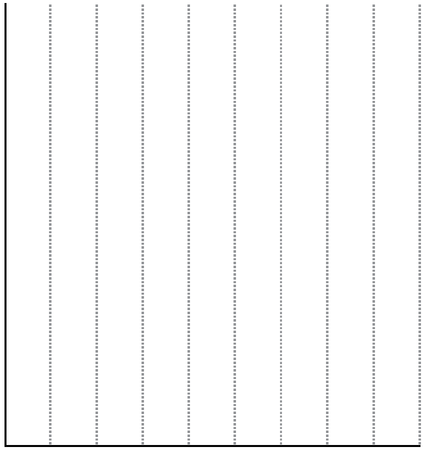

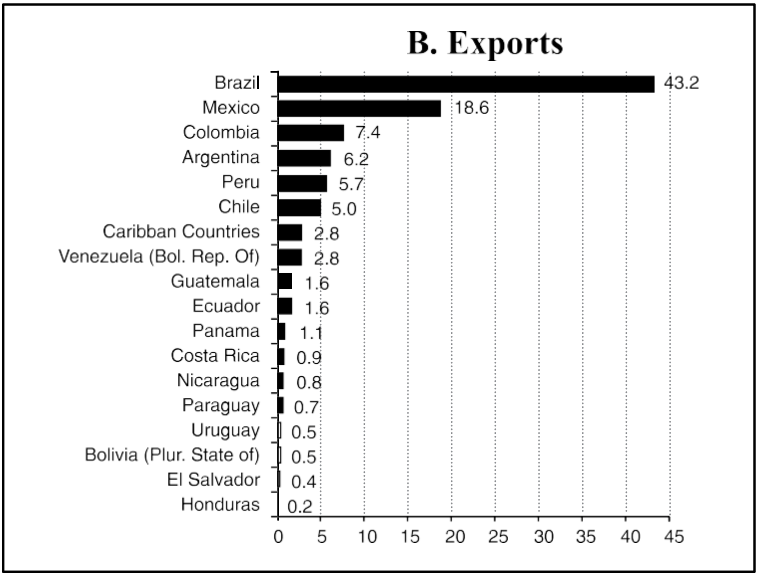

स्रोतः यूएन-ईसीएलएसी

अन्यों के साथ एलएसी क्षेत्र में निवेश करने वाले मुख्य भारतीय निवेशक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, रैनबैक्सी, डॉ रेड्डीज लैब्स, रिलायंस एवं ओएनजीसी विदेश रहे हैं। अभी भी 15 बिलियन डॉलर की समेकित भारतीय एफडीआई 1995 से क्षेत्र का मात्र 2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। भारत ने जितना पिछले 15 वर्षों में एलएसी में निवेश किया है, चीन ने उसके बराबर एलएसी में एक ही वर्ष (2011) में निवेश किया है।

एकल अंकों में उल्लेखनीय सौदों की संख्या के साथ, एलएसी देशों से भारत में निवेश न्यूनतम रहा है। इनमें ब्राजीली बस निर्माता कंपनी मार्कोपोलो के साथ टाटा मोटर्स का संयुक्त उपक्रम शामिल है जिसके विकास केंद्र की स्थापना ब्राजील की कंपनी स्टेफानीनी द्वारा की गयी है और मैक्सिको की कंपनी सिनेपोलिस द्वारा स्थापित सिनेमा मल्टीप्लेक्स शामिल है। पिछले दशक में मल्टीलेटीनाज (लैटिन अमेरिकन मल्टीनेशनल कारपोरेशनों) की उत्साहवर्धक वृद्धि के साथ दक्षिण-दक्षिण निवेश उछाल के सामान्य रूझानों के दौरान ये आकड़े बहुत अधिक हो सकते थे। इस रुझान का एक मुख्य

चालक इस कारक को माना जा सकता है कि सफल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुपातहीन संख्या ऊर्जा , खनिजों और कृषि क्षेत्रों में केंद्रित है, जिसमें भारतीय बाजार ने विदेशी निवेश के लिए सीमित अवसर प्रदान किए हैं।

राष्ट्र-से-राष्ट्र एवं निजी क्षेत्र पहलें

भारत-एलएसी आर्थिक संबंधों के तीव्र विस्तार में व्यापार और निवेश की सुविधा प्रदान करने वाले राष्ट्र-से-राष्ट्र संपर्क महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। अत्यधिक मजबूत संबंधों में , इसने अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) का रूप ले लिया है। भारत और दक्षिणी शंकु आर्थिक ब्लॉक मर्कोसुर ने 2004 में एक पीटीए पर हस्ताक्षर किए थे जो 2009 में लागू हुआ। पीटीए कम से कम 10 प्रतिशत की दरों की कटौती के साथ 450 उत्पादों के लिए अधिमान्य पहुंच प्रदान करता है। भारत और चिली ने 2005 में (2007 से लागू) एक पीटीए पर हस्ताक्षर किए और इसे एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में विस्तारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। वर्तमान समझौता कुल 474 उत्पादों के लिए 10 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच दर रियायतें प्रदान करता है। भारत और पेरू

ने हाल ही में एक पीटीए पर बातचीत शुरू की है। पीटीए के अलावा मेक्सिको, अर्जेंटीना और उरुग्वे के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौतों (बीआईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चिली और वेनेजुएला के साथ बातचीत को जारी रखने के साथ ब्राजील, कोलंबिया और उरुग्वे के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय राज्य और निजी क्षेत्र ने भारत-एलएसी व्यापार और निवेश को सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए कदम उठाए हैं। 1997 में वाणिज्य मंत्रालय ने 'फोकस: एलएसी' कार्यक्रम शुरू किया, जिसकी अवधि हाल ही में 2014 तक बढ़ा दी गई है। यह कार्यक्रम एलएसी क्षेत्र की क्षमता पर भारतीय व्यापार और वाणिज्य निकायों और निर्यात-आयात एजेंसियों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। इसने इस क्षेत्र के लिए भारतीय निर्यात के विस्तार के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और सॉफ्टवेयर और रसायन और दवा उत्पाद की पहचान की है। इस पहल के एक भाग के रूप में भारतीय निजी क्षेत्र, भारत को लैटिन अमेरिका में बढ़ावा देने के लिए, सेमिनार, क्रेता-विक्रेता बैठकों और व्यापार मेलों के

प्रायोजन में शामिल हुआ है। प्रमुख व्यापार मंडल , भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) ने व्यापार प्रस्तावों को उत्प्रेरित करने के लिए चार भारत-एलएसी सम्मेलन आयोजित किए हैं। भारत के रतन टाटा और पेट्रोब्रास के प्रमुख जोस गेब्रियल ने 2007 में आर्थिक संबंधों को प्रगाढ करने के लिए भारत-ब्राजील 'सीईओ मंच' की स्थापना की।

देशों और संयुक्त भारत-एलएसी के प्रमुखों की बैठकें संबंधों को स्फूर्ति प्रदान करने वाला दूसरा रास्ता रहा है। 1970 और 1980 के दशक के दौरान मंदी के बाद, द्विपक्षीय यात्राओं को अगले दो दशकों में बढ़ावा मिला। इस संबंध में ब्राजील ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया जहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत की तीन यात्राएं कीं और इसी के क्रम में दो बार भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उनके देश की यात्राएं की गईं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने पिछले एक दशक में दो बार भारत का दौरा किया। अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली और कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी अपनी यात्राएं निष्पादित कीं। भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 2013 में इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए उम्मीदवारों की सूची में थे।

मुख्य क्षेत्र

भारत-एलएसी व्यापार में विशेष ध्यान देने योग्य गैर-रक्षा क्षेत्र - ऊर्जा, खनिज, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन, कृषि व्यवसाय, आईटी/आईटीईएस, विनिर्माण और उपभोक्ता सामान और आईटी/आईटीईएस हैं। निम्नलिखित अनुभाग इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करेंगे।

ऊर्जा

भविष्य में असीम संभावनाओँ के साथ ऊर्जा भारत और एलएसी के बीच व्यारप और निवेश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तेल क्षेत्र मे एलएसी से आयात 2005 के 0.5 प्रतिशत से 2011 में 2011 तक कुल 9 प्रतिशत तक जा चुका है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भारत वेनेजुएला, ब्राजील, कोलंबिया और क्यूबा के साथ मुख्य इक्विटी और/अथवा व्यापार संबंधों में शामिल हो चुका है। क्षेत्र में तेल की महाशक्ति के रूप में सर्वाधिक पेट्रोल का भंडारण करने वाला वेनेजुएला भारत का मुख्य केंद्र रहा है। ओएनजीसी विदेश एवं वेनेजुएला की देश-आधारित तेल कंपनी पीडीविएसए का संयुक्त उपक्रम आने वाले वर्षों में 2.6 अमेरिकी डालर के निवेश में शामिल हो चुके हैं जिसमें 2016 तक उत्पादन परियोजनाएं 85,000 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) तक

पहुँच चुकीं हैं।

तेल और गैस के संयुक्त उपक्रमों (गहरे पानी के क्षेत्रों सहित) में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ब्राजील के साथ भारत का ऊर्जा संबंध बहुआयामी है, जिसकी प्रतिपूर्ति में रिलायंस द्वारा तेल आयात के बदले में डीजल निर्यात किया जाता है, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल के रूप में है। भारत में ब्राजील से आयात किये जाने में कच्चा तेल सबसे बड़ा भाग है। ब्राजील और भारत ने बायोएथेनॉल और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की शुरुआत की है। ये दोनो देश परमाणु ऊर्जा पर भी बात-चीत कर रहे हैं। भारत ने अर्जेंटीना के साथ एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए है जो कि एकमात्र एलएसी देश है जिसके साथ इस तरह का समझौता हुआ है।

बाकी एलएसी देशों में ओएनजीसी विदेश ने 600 अमेरिकी डॉलरों से अधिक का निवेश कोलंबिया के तेल एवं गैस के संयुक्त उपक्रम में किया है तथा कुछ क्षेत्रों में तेल का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। रिलायंस और एस्सार कोलंबिया से कच्चा तेल आयात करते हैं। भारत की स्टीलनिर्माता कंपनी मोन्नेट इस्पात कोलंबिया की कोयले की खदानों में एक बडे

भूभाग को अधिगृहित करने के बहुत नजदीक है और एस्सार ने हाल ही में देश के स्वामित्व वाली कंपनी ईकोपेट्रोल के साथ कच्चे तेल के आयात का सौदा किया है। रिलायंस ऊर्जा नें कोलंबिया में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलरों का निवेश किया है, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप 1 बिलियन अमेरिकी डॉलरों की कोलंबिया की कोयले की खदानों को अधिगृहित करने के लिए बातचीत कर रहा है।

क्यूबाई तेल और गैस ब्लॉक में भारतीय इक्विटी $ 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है , हालांकि अभी तक किसी भी क्षेत्र में उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। रिलायंस और जिंदल ने पेरू में तेल और गैस अन्वेषण ब्लॉक का अलग-अलग अधिग्रहण किया है। ओएनजीसी विदेश कथित तौर पर इक्वाडोर में देश के स्वामित्व वाली ऊर्जा निगम के साथ साझेदारी में तेल ब्लॉको के अधिग्रहण के लिए बोली लगा रही है। हालांकि , उत्पादन के बंटवारे की अनुमति देने के लिए इक्वाडोर की अनिच्छा ने देश में भारतीय निवेश को सीमित कर दिया है।

कैरेबियाई क्षेत्र में गैस अधोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) त्रिनिडाड एवं टोबैगो, एक मुख्य वैश्विक एलएनजी निर्यातक में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विचार

कर रहा है। स्पॉट और अल्पकालिक त्रिनिडाडियन एलएनजी को वर्तमान में अटलांटिक एलएनजी से भारत द्वारा आयात किया जा रहा है। ओएनजीसी विदेश ने 2005 में त्रिनिदाद और टोबैगो में प्राकृतिक गैस भंडार में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। जिसमें कि एलएसी में भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा (37 प्रतिशत) गैर-कच्चा पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों का है।

एलएसी के द्वारा भारत के ऊर्जा क्षेत्र में न्यूनतम निवेश हुआ है इसके अंतर्गत केवल उल्लेखनीय मामला आंध्र प्रदेश में गैस क्षेत्रों को फैलाने कि लिए 2007 में एक संयुक्त ओएनजीसी- पेट्रोब्रस उद्यम है। हालांकि, पेट्रोब्रास 2010 में इस उद्यम से बाहर निकल गया।

खनिज पदार्थ

लैटिन अमेरिका भारत को खनिज पदार्थों का आयात करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। व्यापार मूल्य के आधार पर यह व्यापार अपने-आप में, मुख्यतः चिली और कुछ ब्राजील और पेरू से किए गए आयात में, 2010 में लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अयस्क आयात में पूर्णतः कॉपर को समाहित करता है। लौह अयस्क 2010 में आयात किए गए 83.5

मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है जिसे ज्यादातर मेक्सिको (यद्यपि यह भारत के कुल खनिज पदार्थों के आयात के पाँचवे भाग का प्रतिनिधित्व करता है।) से किया गया था। अन्य मिश्रित खनिजों जैसे जस्ता , चांदी और मोलिब्डेनम अन्य आयात स्रोतों के रूप में पेरू और बोलीविया को रखा गया हैं।

लैटिन अमेरिकी खनिज क्षेत्र में इक्विटी निवेश में हाल ही में भारतीय निगमों की रुचि बढ़ी है। एस्सार नें 2005 में त्रिनिडाड और टोबेगो में प्रमुख स्टील संयंत्र की स्थापना की योजना की घोषणा की थी हालांकि बाद में वित्तीय समस्याओं और पर्यावरणीय विरोधों के कारण यह सौदा समाप्त कर दिया गया। एक अन्य प्रारंभिक प्रस्तावक जिंदल स्टील एंड पावर था, जिसने बोलीविया के ईएल मुटुन क्षेत्र में बड़े लौह अयस्क भंडार के आधे हिस्से का दोहन करने के लिए आठ वर्षों में 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए बोलीविया सरकार के साथ एक समझौते की घोषणा की। यह लैटिन अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय निवेश था जिसके

अंतर्गत समझौते में एक ऊर्जा संयंत्र का निर्माण और स्टील और स्पंज आयरन के निर्माण को भी निर्धारित किया गया था जो कि बोलिविया के राजकोष में वृद्धि करता। यह समझौता 2009 में लागू हुआ , लेकिन उस वर्ष 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा जिंदल से पूरा नहीं हो सका। बोलिवियाई सरकार ने प्रारंभ में 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रदर्शन बांड को भुनाया और अंततः 2012 में समझौते को रद्द कर दिया। जिंदल बोलिवियाई सरकार को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की कार्यवाही में ले ले गए।

कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदल-बोलीविया विवाद को आखिर कैसे हल किया जाता है , इसने भारतीय निवेशकों और लैटिन अमेरिकी सरकारों को प्रमुख निवेश समझौतों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की चेतावनी दी है। एल मटन मामले में , जिंदल का तर्क है कि बोलीविया सरकार ने प्राकृतिक गैस की आवश्यक मात्रा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और समय पर महत्वपूर्ण सड़क संपर्क को पूरा करने में विफल रहा। मोरालेस सरकार ने जिंदल पर वैश्विक बाजारों में आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए एक समझौते

के रूप में इस सौदे के साथ बुरे विश्वास में निवेश का आरोप लगाया।

कृषिव्यवसाय

एलएसी क्षेत्र बहुतायत में अप्रयुक्त उपजाऊ भूमि और पानी से भरा हुआ है जबकि भारत में इन दोनों का ही जनसांख्यिकीय दबाव (चित्र 3) अधिक हैं। इस मजबूत पूरक का तात्पर्य है कि कृषि व्यवसाय इस क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार के लिए एक प्राकृतिक क्षेत्र है।

अपनी विशेष प्रकार के गेहूं की आपूर्ति के साथ मेक्सिको भारत की हरित क्रांति में एक प्रारंभिक प्रदाता रहा है और भारत ने अर्जेन्टीना से 1946 में खाद्य संकट के साथ अनाज की महत्वपूर्ण आपूर्ति प्राप्त की थी। अर्जेंटीना गेहूं के आयात का एक स्रोत है। हालाँकि वर्तमान में भारत को इसका मुख्य निर्यात खाद्य तेल (मुख्य रूप से सोया और सूरजमुखी) है , जो भारत को अर्जेंटीना के कुल निर्यात का लगभग तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है।

ब्राजील भारत को चीनी, गुड़ और शहद का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है।

चित्र 3: भारत, चीन और लैटिन अमेरिका के लिए 2005 में प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था।

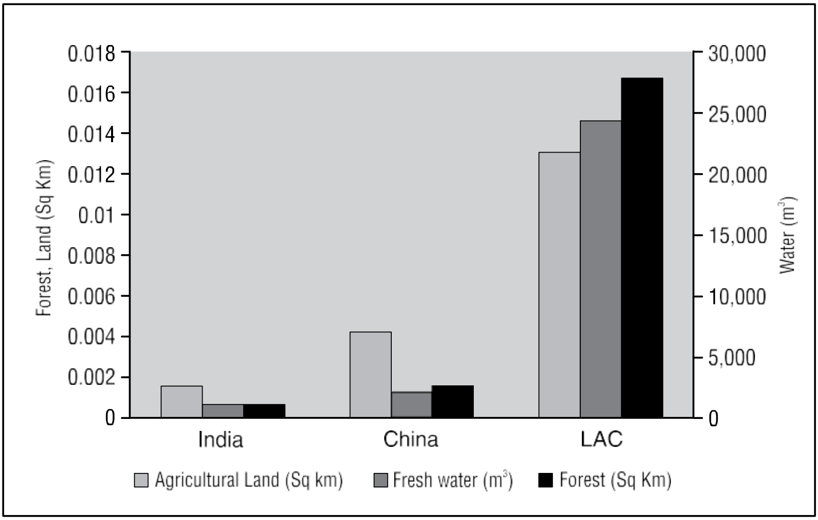

स्रोत: इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, 2010

एलएसी में कृषि व्यवसाय क्षेत्र में एक उल्लेखनीय भारतीय निवेशक रेणुका शुगर्स हैं, जिनकी सात में से चार चीनी की मिलें ब्राजील में स्थित हैं।

कृषिव्यवसाय में भारत-एलएसी संबंध के रूप में सहक्रियाशीलता के लिए प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में संभावित

संघर्ष भी मौजूद हैं। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में एलएसी की 'कृषि महाशक्तियां' जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील ने इस क्षेत्र में उदारीकृत व्यापार की तलाश करते हैं। हालाँकि , भारत 600 मिलियन से अधिक नागरिकों की आजीविका दांव पर होने के साथ कृषि में अपनी उच्च दरों को समाप्त करने के लिए अवरोधी है। यह उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां भारत और कुछ एलएसी देशों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं।

औषधियां एवं रसायन पदार्थ

औषधियां और रसायन पदार्थ विश्व व्यापार में भारत की प्रमुख ताकतें हैं। भारतीय फार्मा उद्योग विश्व को जेनेरिक की आपूर्ति में एक अग्रणेता के रूप में उभरा है और एलएसी भी इसका कोई अपवाद नहीं है। यह क्षेत्र भारत के एलएसी क्षेत्र को लगभग 15 प्रतिशत निर्यात का प्रतिनिधित्व करता है , जो कि इस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनाता है और मात्र परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के बाद दूसरे नंबर पर आता है।

कई भारतीय दवा कंपनियां एलएसी में निवेशक और नियोक्ता हैं। रैनबैक्सी ने 2000 में ब्राजील में एक अग्रणी के तौर पर प्रवेश किया था , डॉ। रेड्डी की प्रयोगशालाओं ने मेक्सिको में एक संयंत्र का अधिग्रहण किया तथा ग्लेनमार्क ने अर्जेंटीना और ब्राजील में निवेश किया है। जायडस - कैडिला ने

ब्राजील की दो दवा कंपनियों का अधिग्रहण किया और अब वह बाजार में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारतीय निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता ब्राजील है, इसके बाद अर्जेंटीना, मैक्सिको, पेरू और कोलम्बिया आते हैं।

फार्मास्यूटिकल्स में रणनीतिक जुड़ाव की शुरुआत का संकेत देते हुए, भारत और ब्राजील ने जेनेरिक व्यापार पर यूरोपीय संघ के अवैध दबदबे से लड़ने में सहयोग किया है। इस क्षेत्र की चुनौतियों में अर्जेंटीना में तेजी से संरक्षणवादी नीतियां शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय फार्मा उद्योग के विकास को बाधित किया है।

आईटी/आईटीईएस

आईटी/आईटीईएस में भारत का वैश्विक नेतृत्व भली-भांति से स्थापित हो चुका है। एलएसी के संबंध में, इसके विपरीतार्थ, अन्य रास्तों की मौजूदगी के अलावा यह एफडीआई का अमुगामी व्यापार का एक मामला मात्र है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) के नेतृत्व के अधीन जिसने अपनी निकटवर्ती रणनीति के तौर पर एलएसी क्षेत्र में बहुत पहले 2001 में प्रवेश किया था

के साथ एलएसी क्षेत्र में क्रमानुसार भारत की कंपनियों की मौजूदगी में विप्रो, इंफोसिस, महिंद्रा सत्यम, जैनपैक्ट तथा इवालूसर्वे शामिल हैं। वर्तमान में एलएसी क्षेत्र में 25 भारतीय आईटी/आईटीईएस कंपनियां मौजूद हैं। भारतीय आईटी/आईटीईएस कार्पोरेशनों ने ब्राजील, मेक्सिको, उरूग्वे, अर्जेन्टीना, चिली, कोलंबिया एवं पेरू सहित अनेक देशों में मौजूदगी सहित, 20,000 लैटिन अमेरिकियों को रोजगार मे लगा रखा है। इनमें सबसे बडी मात्रा टीसीएस के पास है। जैसा कि फार्मास्यूटिकल्स में है , भारत आईटी/आईटीईएस में एलएसी के साथ एक व्यापार अधिशेष चलाता है जो प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में व्यापार घाटे की भरपाई करने में मदद करता है।

विनिर्माण और उपभोक्ता सामान

भारत एलएसी क्षेत्र में आटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों के साथ बड़ी मात्रा में विनिर्माण और उत्पादों का निर्यात करता है। ऑटोमोटिव क्षेत्र में ब्राजील, अर्जेन्टीना, कोलंबिया और चिली भारत के लिए तेजी से बढ़ते बाजारों में से हैं। टाटा तथा फिएट संयुक्त रूप से कोरडोबा, अर्जेन्टीना में पिक-अप ट्रकों का निर्माण करता है। ब्राजील के

एयरोस्पेस में अग्रणी एम्ब्रेयर भारतीय बाजार में कॉर्पोरेट जेट की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

भारतीय गोदरेज समूह ने 2010 में अर्जेंटीना की दो कंपनियों का अधिग्रहण किया और इसके बाद 2012 में चिली की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रसाधन निर्माता कंपनी कॉस्मेटिका नेशियोनाल में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया। भारत में एलएसी निवेश के एक दुर्लभ मामले में , टाटा मोटर्स और ब्राज़ीलियाई बस निर्माता मार्कोपोलो ने भारत में बसों के निर्माण के इस क्षेत्र में 50-75 मिलियन अमेरिकी डॉलरों के शुद्ध निवेश के साथ 2006 में एक संयुक्त उद्यम की पहल की। इस संबंध में उत्तेजकों के तौर पर ब्राजील में पीईटी फिल्मों, जरी यार्न, नाइट्राइल रबर और स्टेनलेस स्टील जैसे कई भारतीय उत्पादों पर ब्राजील द्वारा लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क शामिल हैं।

निष्कर्ष

व्यापार और निवेश, वर्तमान भारत-एलएसी संबंधों का मूलमंत्र है। भारत और एलएसी, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों , फार्मास्यूटिकल्स और व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्रों में एक-दूसरे

के अधिकाधिक पूरक हैं। व्यापार साझेदारों का विविधीकरण और नए बाजारों तक पहुँच दोनों भागीदारों के लिए भी एक प्राथमिकता है और वह भी विशेष रूप से पश्चिमी मांग वित्तीय संकट के अंदर में स्थिर हो जाती है। इन रुझानों और प्रचालकों को देखते हुए इस ओर विश्वास करने का हर कारण है कि भविष्य में आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ेंगे।

अधिक आर्थिक संबंधों की चुनौतियों में एक-दूसरे की कमजोर समझ शामिल है , जिसमें भारत में स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा कौशल में एक बड़ी कमी और एलएसी के कुछ हिस्सों में अंग्रेजी की दक्षता में कमी शामिल है। यहां परिवहन संपर्कता निश्चित रूप से कमजोर है और हालांकि कुछ हवाई सेवाओं के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं फिर भी, भारतीय शहरों से अधिकांश एलएसी राजधानियों तक उड़ान भरना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। एलएसी के दृष्टिकोण से उच्च भारतीय दरें, विशेष रूप से कृषि में , व्यापार को अधिकाधिक बढ़ाने में बाधा हैं। भारतीय दृष्टिकोण से , बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अभी तक भारतीय बाजार में अवसरों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

यहां पर प्रतियोगिता के संभावित क्षेत्र भी मौजूद हैं। क्षेत्र-वार,

प्रमुखतः एक क्षेत्र विनिर्माण है। विश्व स्तर पर , चीन इस क्षेत्र में एलएसी का प्रमुख प्रतियोगी है। हालाँकि , वैश्विक व्यापार में भारतीय विनिर्माण का योगदान अभी तक नगण्य रहा है, लेकिन इसके विपरीत यह कहना उचित होगा कि, मेक्सिको , लेकिन यह तेजी से बदलने लगा है , विशेषकर मध्यम-प्रौद्योगिकी स्थान जैसे कि ऑटोमोटिव उद्योग में। संभावना है कि अनिवार्य तौर पर अपने बड़े पैमाने पर कृषि कार्यबल को रोजगार प्रदान करने के परिणामस्वरूप अगले दो दशकों में वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में भारत का उदय होगा। आवश्यक सुधारों को प्रयोग में लाने का ध्यान रखते हुए , भारत तब विनिर्माण क्षेत्र में एलएसी के अग्रेताओं, विशेष रूप से मेक्सिको के लिए विनिर्माण क्षेत्र में एक बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रदान कर सकता है। जिन क्षेत्रों में भारत एक वैश्विक अग्रेता है जैसे कि आईटी/आईटीईएस और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को निकट भविष्य में एलएसी द्वारा पकड़ने की संभावना नहीं है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में भारतीय निर्यात एलएसी से अधिक परिमाण के एक आदेश से अधिक है।

एलएसी ऊर्जा, खनिज और कृषि व्यवसाय जैसा कि ऊपर वर्णित है जैसे प्राथमिक उत्पादों में एक वैश्विक नेता है। यद्यपि भारतीय बाजारों में इन क्षेत्रों में एलएसी देश, अन्य देशों (जैसे आसियान और ऑस्ट्रेलिया) के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन कई वस्तुओं की आपूर्ति में वैश्विक तंगी का अर्थ

यह होगा कि आने वाले वर्षों में भारत से उनके निर्यात में मजबूत वृद्धि होगी। हालांकि , भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार एकीकरण एलएसी की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है। इस प्रकार, भविष्य में एलएसी देशों के एशिया में कुछ प्राथमिक उत्पादों में भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा से बाहर होने की संभावना है।

अंत में, जिंदल-बोलीविया सौदे का पतन संबंधों में वृद्धि के लिए एक बाधा अवरोध का संकेत हो सकता है। भारतीय निगमों को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि लैटिन अमेरिका भूतकाल की भंयकर तानाशाही के बाद एक लंबा सफर तय कर चुका है। एलएसी क्षेत्र के वाम राजनैतिक झुकाव (हालांकि अलग-अलग तीव्रता के साथ) का अर्थ है समावेशी विकास सहित एलएसी सरकारों के लिए एक बहुत ही उच्च प्राथमिकता। भारतीय निगम जो पूर्व और विस्तृत राजनीतिक जोखिम मूल्यांकन का संचालन नहीं करते हैं और एलएसी में अत्यधिक भीड़ वाले राजनीतिक कारकों से इस क्षेत्र के लिए अपनी निवेश योजनाओं में स्थानीय समुदायों के विकास को शामिल करने में विफल रहते हैं तो उनकी ओर से एलएसी देशों को भारत में एक विविध आर्थिक साझेदार के रूप में विश्वास नहीं खोना चाहिए ,

जो उन्नत स्तर की प्रौद्योगिकी, मानव पूंजी और संभावित रूप से बड़े पैमाने पर बाजार प्रदान करता है।

अगला खंड एलएसी के साथ भारत के उन संबंधों का परीक्षण करेगा जो पूर्णरूप से आर्थिक तथा राजनीति, रणनीति और सैन्य को शामिल करती है।

राजनीतिक और रणनीतिक संबंध

जैसा कि हमने इस लेख के पिछले भाग में देखा था , भारत-एलएसी राजनीतिक भागीदारी भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरी के कारण और यह तथ्य कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अधिकांश एलएसी देश वैचारिक रूप से अलग थे, ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। दक्षिण-दक्षिण ढांचे की बढ़ती हुई क्षमता ने संपर्क की शर्तों को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है। निम्नलिखित खंड वर्ष 2000 के बाद की अवधि में द्विपक्षीय संबंधों , क्षेत्रीय संपर्क और रक्षा और अंतरिक्ष संबंधों का विश्लेषण करेंगे, इसके बाद राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों की विषय-वस्तु और प्राथमिकताओं पर निष्कर्ष प्रदान किया जाएगा।

द्विपक्षीय संबंध

भारत ने पारंपरिक रूप से एलएसी को देश-दर-देश द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से मुख्य रूप से जोड़ा है और यह वर्तमान में भी सत्य है, हालांकि क्षेत्रीय संपर्क ऊपर की ओर (नीचे देखें) पर हैं। 1991 के बाद की अवधि में लैटिन अमेरिका का एक स्थायी लोकतांत्रीकरण और दोनों क्षेत्रों में एक बाह्य आर्थिक नीति देखी गई , जिसने गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को समर्थन दिया। 2000 के बाद की अवधि को द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों में एक प्रमुख परिवर्तन के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए , नई दिल्ली स्थित एलएसी मिशनों की संख्या 2002 में 12 से बढ़कर 2011 में 18 हो गई और इस क्षेत्र में भारत के मिशन 7 से बढ़कर 14 हो गए हैं। 2001 से पहले के 50 साल में प्रमुखों की 12 यात्राओं से अगले एक दशक में 2011 तक प्रमुखों की यात्राओं की संख्या 12 हो गई।

भारत का एलएसी में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध ब्राजील के साथ है। यह चौंकाने वाली बात नही है , क्योंकि ब्राजील एक गतिशील और विश्व स्तर पर उन्मुख विदेश नीति के साथ एलएसी का सबसे बड़े देश और

अर्थव्यवस्था है। वर्तमान संबंधों के मुख्य तत्व ऊर्जा, खनिज, कृषि व्यवसाय और फार्मास्यूटिकल्स, एक उभरते रक्षा संबंध, साथ ही दक्षिण-दक्षिण और वैश्विक शासन में द्विपक्षीय और ब्रिक्स और आईबीएसए के तत्वावधान में बढ़ते आर्थिक संबंध हैं।

शीत युद्ध के वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत दूर के संबंध के बाद, 1996 में राष्ट्रपति फर्नांडो एनरिक कार्डसो की भारत की अभूतपूर्व यात्रा के बाद से दोनों राज्यों के बीच संबंध काफी अच्छे हो गए थे। स्वास्थ्य मंत्री जोस सेरा द्वारा भारत सरकार और इसके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ब्राज़ील में जेनेरिक के लिए बड़े पैमाने पर अवसरों के सफल प्रयासों के लिए यह स्वास्थ्य सुरक्षा की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल थी।

राष्ट्रपति कार्डसो के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति लूला विकासशील दुनिया के लिए एक मजबूत आवाज के उत्साही प्रस्तावक थे और उन्होंने 2003 में आईबीएसए की स्थापना में भाग लिया। राष्ट्रपति लूला ने 2003 के बाद भारत के साथ 'रणनीतिक साझेदारी' के निर्माण के लिए तीन बार भारत का दौरा किया। भारत-ब्राजील संबंधों का विस्तार करने का श्रेय मोटे तौर पर

इस ऊर्जावान और दूरदर्शी ब्राजील के नेता को जाता है। उनकी उत्तराधिकारी दिल्मा रूसेफ ने 2012 में एक यात्रा के साथ प्रवृत्ति जारी रखी है, जिसके दौरान 2015 में द्विपक्षीय व्यापार के लिए लक्ष्य 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया गया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में ब्राजील का दौरा किया, उसके बाद 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने।

भारत और ब्राजील के संबंधों का श्रेय निश्चित रूप से इस दूरदर्शी ब्राजीली नेता को जाता है। उनके उत्तराधिकारी डिल्मा रूसेफ ने भी 2012 में यहां की यात्रा कर इस क्रम के जारी रखा जिस यात्रा के दौरान 2015 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तय किया गया था। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ब्राजील की यात्रा की जिसके बाद 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहां की यात्रा की थी।

मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का परिवर्तन वैश्विक शासन , रक्षा और अंतरिक्ष (नीचे विस्तृत) पर कई ठोस लाभों में हुआ है। यह दोनों देशों द्वारा उनके संबंधों को अलग न करते हुए दक्षिण-दक्षिण अंतःक्रिया को गहरा करने की एक समग्र

परियोजना के हिस्से के रूप में देखा गया था। एक बड़ी क्षमता के साथ सहयोग का विशेष रूप से द्विपक्षीय क्षेत्र नई पीढ़ी, स्थायी विकास, जैव विविधता के उपयोग के माध्यम से संवारे गये 'जैव उद्योग' हैं जो ब्राजील और भारत दोनों के पास बहुतायत में उपलब्ध हैं। इस प्रकार का दूसरा क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा का है। ब्राज़ील और भारत में एक अभिनव स्थिरता प्रतिमान बनाने की क्षमता है जो दोनों के लिए उन्नत वैश्विक नेतृत्व में बदल सकता है।

एलएसी की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में , मेक्सिको में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरने की क्षमता है। यद्यपि (जैसा कि हमने ऊपर देखा है) भारत का आईटी क्षेत्र मेक्सिको में निवेश करने में अग्रणी था फिर भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध हाल ही में प्रगाढ होने प्रारंभ हुए हैं। राष्ट्रपति पाटिल ने 2008 में मैक्सिको का दौरा किया। हालांकि, प्रधान मंत्री सिंह की यात्रा केवल 2012 में सफल हुई और वह भी मात्र जी20 शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी की यात्रा के 26 साल बाद। कुछ इसी प्रकार की स्थिति मैक्सिको की ओर से यात्राओं में भी देखने को मिली जिसमें 2007 में राष्ट्रपति फेलिप काल्डेरन की यात्रा 22 साल के अंतराल के बाद पूरी हुई थी। वृहद अमेरिकी बाजार से निकटता ने अक्सर एशियाई देशों के साथ मेक्सिको को ऊर्जावान संबंधों से विचलित कर दिया है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बदलने लगी है। 2003 से जी20 शिखर सम्मेलनों ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिसमें भारतीय और मैक्सिको के अधिकारी नियमित रूप से मिलते हैं। 2007 की राष्ट्रपति फेलिप कैलडरन की यात्रा ने

अपराध पर प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के निष्पादन किया। आईसीएडब्ल्यू ने 2010 में भारत-मेक्सिको संबंधों पर एक द्वि-राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। भारतीय दूतावास द्वारा एक ठोस प्रयास के बाद भारतीय नागरिकों के प्रति मेक्सिको की प्रतिबंधात्मक वीजा व्यवस्था काफी आसान हो गई। दूतावास ने एक मेक्सिको-इंडिया व्यापार चैंबर भी स्थापित किया। द्विपक्षीय व्यापार के अब 2015 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत और मेक्सिको के बीच कुछ मतभेद हैं, उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में। भविष्य में विनिर्माण क्षेत्र में मेक्सिको के लिए एक प्रतियोगी के रूप में भारत के उभरने की भी संभावना है। फिर भी , सहयोग के कई और नए क्षेत्र मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, मेक्सिको और भारत दोनों के पास गंभीर सशस्त्र आंतरिक चुनौतियों का सामना करने का अनुभव है और ये एक-दूसरे की सफलताओं और भूलों से उपयोगी रूप से तुलना कर सकते हैं और सीख सकते हैं। हाल ही में 2000 के बाद से पूर्ण लोकतंत्र बना मेक्सिको ,

भारतीय लोकतांत्रिक प्रथाओं का अध्ययन करके भी लाभान्वित हो सकता है। इसके अतिरिक्त , मैक्सिको की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास को देखते हुए , एनएएफटीए के माध्यम से अमेरिकी बाजार के साथ इसका घनिष्ठ एकीकरण तथा फला-फूला और बहुआयामी भारत-अमेरिका संबंध से यह प्रतीत होता है कि भारत-मेक्सिको द्विपक्षीय संबंध की पूरी संभावना अभी भी साकार होने से बहुत दूर है।

एलएसी की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अर्जेंटीना के साथ संबंधों को 2009 में राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज की भारत यात्रा ने ऊर्जा प्रदान की थी जो कि 15 वर्षों में पहली बार हुई थी जिसके दौरान दोनों देशों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अर्जेंटीना भी मुंबई में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला केवल दूसरा लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन गया। अर्जेंटीना के वनस्पति तेलों का एक प्रमुख स्रोत के रूप में यह भारत के लिए खाद्य सुरक्षा के संबंध का एक चालक भी है।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की मुहिम पर अर्जेंटीना के साथ राजनीतिक मतभेद मौजूद हैं। अर्जेंटीना ने भारत से लास माल्विनास (फॉकलैंड्स) द्वीपों पर अपना दावा वापस लेने की अपील की है। भारत ने शीत युद्ध के दौरान लास माल्विनास विवाद पर अर्जेंटीना का समर्थन किया था लेकिन वर्तमान में एक तटस्थ रुख अपना लिया है। ओएनजीसी विदेश ने हाल ही में एक ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी से विवादित द्वीपों के पर्यवेक्षण ब्लॉक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक बोली लगाई , हालांकि इस बोली पर अंततः भारत सरकार ने रोक लगा दी थी।

वेनेजुएला एलएसी में अपने तेल के भंडारों के साथ जो कि अब सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ चुका है उसके साथ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रत्याशित रूप से भारत-वेनेजुएला संबंधों में ऊर्जा सुरक्षा (ऊपर देखें) हावी रही हैं। ह्यूगो शावेज के शासन में, वेनेजुएलाद एक वैचारिक देश भी है , जिसके अमेरिका के वर्चस्व के सापेक्ष एक कार्डिनल फॉरेन पॉलिसी लक्ष्य का विरोध और पड़ोसी कोलंबिया के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। भारत ने आम तौर पर राष्ट्रपति शावेज़ के अधिक संवेदनशील बयानों से खुद को दूर कर लिया है और एक व्यावहारिक संबंध को सफलतापूर्वक बनाए रखा है।   राष्ट्रपति शावेज़ की भारत की यात्राओं की उल्लेखनीय संख्या (1999 के बाद से अब तक चार) के बदले अब तक भारतीय राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री द्वारा एक भी यात्रा नही की जा सकी है। हालांकि, वेनेज़ुएला के मर्कोसुर में प्रवेश करने और वेनेजुएला में भारतीय निवेशों के विस्तार के साथ, नई दिल्ली को एक राजनीतिक निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष उत्पन्न न हो सके।

मात्र पिनोशे युग के अपवाद के साथ, भारत के चिली के

साथ लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। पिछले दो दशकों में हालांकि चिली के इस क्षेत्र में सबसे समृद्ध देश के रूप में उभरा है लेकिन, फिर भी यह संबंध मजबूती से मजबूती की ओर बढ रहा है। दो राष्ट्रपति की यात्राओं (2005 में रिकार्डो लागोस और 2009 में मिशेल बाचेलेट) के सापेक्ष 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यहाँ की यात्रा की है। चिली ने स्थायी यूएनएससी सदस्यता सीवाई के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है

एलएसी में मध्यम स्तर की अर्थव्यवस्था वाले कोलंबिया के साथ भी भारत के संबंध बढ़ रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा इस संबंध का एक प्रमुख चालक है , क्योंकि कोलंबिया तेल और कोयले से समृद्ध है , लेकिन यहाँ रक्षा , पर्यटन और शिक्षा की भी अंतर्निहित क्षमता है। राष्ट्रपति एंड्रेस पास्ट्राना की 2001 की यात्रा को अभी तक भारत द्वारा एक समतुल्य स्तर की यात्रा के द्वारा बराबर नहीं किया गया है। 2012 में भारत और कोलम्बिया दोनों गैर-स्थायी यूएनएससी सदस्य हैं जिसने अधिक संपर्क की सुविधा प्रदान की है। दोनों देश आतंकवाद के शिकार भी हैं। कोलम्बिया अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सहमति (सीसीआईटी) को शीघ्र अपनाने

की भारत की मांग का समर्थन करता है।

क्यूबा एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ भारत का शीत युद्ध के दौरान विशेष रूप से अच्छा संबंध रहा है। वर्तमान अवधि में यह संबंध अधिक व्यावहारिकता के साथ चिह्नित है जिसका मुख्य घटक ऊर्जा सुरक्षा है। शीत-युद्ध के बाद की दुनिया में , क्यूबा दक्षिण-दक्षिण राजनीतिक भागीदारी का एक मजबूत समर्थक है यह एक ऐसी स्थिति है जो भारतीय विदेश नीति के पहलुओं में गूंजती है।

वे अन्य एलएसी देश जिनके पास राजनीतिक संबंधों में विस्तार के लिए प्रमुख संभावनाएं हैं उनमें अपनी बड़ी खनिज संपदा और उच्च विकास दर के साथ पेरू शामिल है तथा इसी कारण से बोलीविया , और औपनिवेशिक काल में अधिक भारतीय प्रवासियों के कारण कुछ कैरिबियन देश जैसे कि गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल हैं। कैरेबियाई देशों के भारतीय मूल के देशों के प्रमुखों और अन्य प्रतिनिधियों ने पहले ही भारत की कई यात्राएं की हैं। अंग्रेजी बोलने वाले कैरेबियाई देशों के साथ एक विस्तारित भारतीय राजनीतिक संबंध के लिए संस्कृति , खेल और पर्यटन एक

मजबूत आधार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने ऊपर देखा है , ऊर्जा, भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है।

क्षेत्रीय संपर्क

अगस्त 2012 में नई दिल्ली पहली इंडिया-सेलाक ट्रोइका विदेश मत्री सम्मेलन का आयोजन केंद्र था। विदेश मत्री एस. एस कृष्णा, वेनेजुएला और चिली के विदेश मत्रियों जो नवगठित एलएसी क्षेत्रीय समूह, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के समुदाय, जिसे इसकी स्पेनी-भाषा में सेलाक के नाम से जाना जाता है का प्रतिनिधित्व कर रहे थे से मुलाकात की। सेलाक अपने आप में इसलिए अद्‌वित्तीय है कि यह वहाँ के सभी 33 संप्रभु देशों को अपने क्षेत्रीय समूह में शामिल करता है।

महत्वपूर्ण ढंग से सेलाक प्रमुखों नें जुड़ने के लिए सबसे पहले भारत का चुनाव किया और उसके बाद चीन को। शिखर सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य में ऊर्जा खनिज, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोगों से लोगों का संपर्क , आतंकवाद, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग जैसे मामलों पर जोर दिया गया। विशिष्ट परिणामों के संदर्भ में भारत और सेलाक एक 'रणनीतिक साझेदारी का गठन करने पर सहमत हो गये और उन्होंने व्यापारिक आर्थिक विकास मंच, एक कृषि कार्य समूह और एक ऊर्जा मंच की स्थापना करने का निर्णय लिया। मान लें कि सेलाक एक गतिशील क्षेत्रीय इकाई के रूप में सफल होता है जो एलएसी के भीतर एकीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार बनता, है न

शिखर सम्मेलनों की संभावना है जो आने वाले वर्षों में भारत और एलएसी के राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएं।

सेलाक के अलावा, भारत एक अन्य प्रमुख एलएसी क्षेत्रीय संगठन, मरकोसुर के साथ संपर्क में रहा है। अर्जेंटीना , उरुग्वे, ब्राजील और हाल ही में वेनेजुएला के दक्षिणी कोने के देशों के लिए आम बाजार के रूप में, मर्कोसुर मुख्य रूप से एक आर्थिक ब्लॉक है, यही कारण है कि भारत के साथ हस्ताक्षरित पीटीए इस संबंध की आधारशिला है। हालाँकि , व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण की अपनी परियोजना और इसके सुनिश्चित 'डेमोक्रेसी खंड' के प्रमाण के अनुसार, मर्कोसुर भी सिर्फ व्यापार से भी अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। इस खंड को हाल ही में इसके अध्यक्ष फर्नांडो लुगो के संदिग्ध महाभियोग के बाद सदस्य-राज्य पैराग्वे के निलंबन के दौरान सक्रिय किया गया था।

भारत का अन्य एलएसी क्षेत्रीय समूहों जैसे कि कैरीकॉम (कैरिबियन समुदाय) और सिका (सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन

सिस्टम), और एडियन समुदाय के साथ संपर्क सीमित है। हालांकि, इनकी वजह से अभी तक किसी भी पक्ष को कोई भी बड़ा संस्थागत भुगतान नहीं हुआ है। वर्तमान में वामपंथी वेनेजुएला की अगुवाई वाले आल्बा ब्लॉक, ब्राज़ील-मिडवाइफ़्ड यूनासुर (दक्षिण अमेरिकी राज्यों का संघ) या पारंपरिक रूप से अमेरिका- ओएएस (अमेरिकी राज्यों का संगठन) जैसे अन्य प्रमुख संगठनों के साथ बहुत कम जुड़ाव है।

रक्षा और अंतरिक्ष

रक्षा और अंतरिक्ष भारत-एलएसी संबंधों के एक उभरते रणनीतिक घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत और एलएसी के बीच रक्षा संबंध अपेक्षाकृत हाल की घटना है। हालांकि, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत ने अर्जेंटीना की सहायता की और उसके उपग्रह को लॉन्च करने में मदद की। अंतरिक्ष सहयोग में ब्राजील सबसे मुख्य भागीदार है। भारत और ब्राज़ील ने 2004 में अंतरिक्ष सहयोग पर एक ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत भारत को एक ब्राज़ीलियाई माइक्रो-उपग्रह को लॉन्च करना है और इसके लिए पहले से ही सैटेलाइट डेटा प्राप्त

करने के लिए ब्राजील में ग्राउंड स्टेशन के स्थान का चयन कर दिया है। दोनों देशों ने आईबीएसए समूहों के तत्वाधान में दक्षिण के साथ एक संयुक्त उपग्रह परियोजना भी शुरू की है। यह परियोजना शुरू में मौसम पूर्वानुमान , कृषि और खाद्य सुरक्षा अध्ययन के अध्ययन पर केंद्रित दो उपग्रहों का निर्माण करेगी। ब्राजील ने हाल ही में भारत को अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा है।

एलएसी देशों में भारत के लिए ब्राज़ील प्रमुख रक्षा भागीदार भी है। दोनों देशों ने 2003 में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संबंध की शुरुआत की , जिसमें वैमानिकी, जहाज निर्माण, एकीकृत वायु रक्षा, जंगल युद्ध और रक्षा सॉफ्टवेयर में संयुक्त गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी। भारत ने 2005 में ब्राजील में एक रक्षा सहचारी की तैनात की थी। 2008 में , भारत ने ब्राजील से छह ईएमबी-144 इंटेलीजेंस, टोही और निगरानी विमान का आदेश दिया , जिनमें से पहले विमान को हाल ही में उनके सुपुर्द किया गया है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा आने वाली दुश्मनी मिसाइलों और विमानों की युद्धक्षेत्र निगरानी के लिए अपने रडार को माउंट करने के लिए उपयोग

किया जाएगा। । ब्राजील विमान पर डीआरडीओ रडार को माउंट करने के लिए और मंच के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है।

ब्राजील के अधिकारियों ने सक्षम और गहन प्रक्रिया में गहरी रुचि दिखाई है , जिसके द्वारा भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 126 मीडियम मल्टी-रोल लड़ाकू विमान (एमएमआरसीए) के लिए 18.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मेगा-ऑर्डर का निर्णय लिया, जिसके लिए डसॉल्ट राफेल विमान, विजेता के रूप में उभरा है। ब्राजील के रक्षा मंत्री सेलसो अमोरिम ने भारत से इस तरह के निर्णय लेने के लिए ब्राजील के दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए अपनी खुली निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया को साझा करने के लिए कहा है। भारत ने इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। भारत इस अनुरोध पर सहमत हुआ है। आगे ब्राजील और भारत, भारत के पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए रूस और साइबर-डिफेंस में ब्राज़ील के अनुभव के साथ सह-उत्पादन समझौतों पर जानकारी साझा करने पर चर्चा कर रहे हैं। ब्राज़ील ने अपनी फ्रांसीसी-निर्मित स्कॉर्पीन पनडुब्बियों,

जिसे भारत ने भी तैनात किया है, के लिए नई दिल्ली से स्पेयर पार्ट्स में परिचालन प्रशिक्षण और सहयोग की भी मांग की है।

अन्य एलएसी राज्यों के साथ भारत का रक्षा संबंध प्रारंभिक चरण में है। इक्वाडोर ने 2008 में 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत पर भारत से चार ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर किये थे। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। 2008 में सैंटियागो में अपने दूतावास में रक्षा अटैची रखने के बाद से भारत अपने ध्रुव हैलीकॉप्टरों को चिली को बेचना चाह रहा है। भारत 2009 में कोलंबिया के साथ भारतीय होवित्जर की बिक्री को लेकर भी चर्चा में था, हालांकि इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

जाहिर है, भारत और एलएसी देशों के बीच रक्षा और अंतरिक्ष संबंधों के विस्तार की एक बड़ी संभावना है। एक रणनीतिक प्रकृति के किसी भी द्विपक्षीय संघर्ष की कमी, कई रक्षा क्षेत्रों में संपूरकता और वाणिज्यिक अनिवार्यताएं भविष्य में इस सहयोग को बढ़ाने के लिए मजबूत चालक हैं।

निष्कर्ष

शीत युद्ध के दौरान उनके सीमित स्तरों से भारत और एलएसी के बीच राजनीतिक संबंधों ने एक नवपरिवर्तन बिंदु का अनुभव किया है।

एक लोकतांत्रिक एलएसी के उद्भव और एक बढ़ती बहुध्रुवीय दुनिया जो संचार क्रांति के माध्यम से आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़ी है में भारत के उदारीकरण ने भूतकाल में संबंधों में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख बाधाओं को हटा दिया है। भारत और एलएसी अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ अपने संबंधों के लिए स्वतंत्र हैं।

वर्तमान संबंधों में द्विपक्षीय प्रिज्म प्रमुख है , और एलएसी में क्षेत्रीय एकीकरण के प्रारंभिक चरण को देखते हुए , इस प्रवृत्ति के अगले एक या दो दशकों तक जारी रहने की उम्मीद है। स्पष्ट है , एक महाद्वीपीय या वैश्विक पदचिह्न के साथ बड़े देशों विशेष रूप से ब्राजील और मैक्सिको के साथ संबंध को जारी रखने की व साथ ही अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली और वेनेजुएला के साथ भी एक निरंतर और गहन ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ब्राज़ील के साथ संपर्क वर्तमान में ब्रिक्स, आईबीएसए और बेसिक में अपने आकार और भागीदारी के लिए सबसे अच्छा विकसित धन्यवाद है।

हालांकि, भारत को इस क्षेत्र के विकसित एकीकरण मार्गों , खासकर मर्कोसुर और देशों के आल्बा समूह पर कड़ी नजर

रखने की जरूरत है। सेलाक पहल एक महत्वाकांक्षी विकास है जो दक्षिण एशियाई एकीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान कर सकता है। जब भारत मर्कोसुर के साथ व्यस्त है तो वर्तमान में अल्बा ब्लॉक के साथ एक सार्थक राजनीतिक संबंध की कमी मौजूद है। भारत बहुसंख्यक मंचों, प्रवासी कारकों और संसाधन सुरक्षा की अनिवार्यताओं में वोट करने वाले मित्रों और सहयोगियों की आवश्यकता के कारण करीकॉम या सिका समूहों में कुछ छोटे देशों की उपेक्षा नहीं कर सकता है।

नई दिल्ली में उच्चतम स्तर पर पदासीन राजनीतिक अधिकारियों को अपनी आकस्मिक यात्राओं से परे लैटिन अमेरिका के साथ संपर्क स्थापित करने की भी आवश्यकता है। गहन संबंध की मांग के लिए, कार्यसूची का पूरा अनुगमन,   भारत-एलएसी संबंध को संस्थागत बनाने , कूटनीतिज्ञों के लिए भाषा प्रशिक्षण और आम रणनीतियों पर क्षेत्रीय बातचीत तथा विकासात्मक चुनौतिया जैसे कि आतंकवाद, रक्षा प्रौद्योगिकियों, शहरी नियोजन और गरीबी से निपटना (में से कुछ हैं) की आवश्यकता है।

वैश्वक शासन

हाल के दशकों में आतंकवाद , जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट, मानवाधिकारों, वैश्वीकृत वित्तीय जोखिम

और अन्य के रूप में 'सीमारहित' अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के एक मेजबान का उद्भव अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली एक गंभीर समस्या है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि उनके व्यवस्थित रूप से हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। वैश्विक शासन के इन मुद्दों का अब वैश्विक शक्तियों के सीमित समूह द्वारा समाधान नही किया जा सकता है जैसा कि शीत युद्ध के दौरान किया जाता था , बल्कि इसके लिए अधिकांश विकासशील देशों, नागरिक समाज समूहों और यहां तक कि व्यक्तिगत नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने वैश्विक प्रशासन के मुद्दों पर विविध वैश्विक कारकों के साथ सक्रिय रूप से संबंद्ध बनाया है।

इस खंड में, हम इस क्षेत्र में एलएसी देशों के साथ भारत की भागीदारी को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। ब्राजील , जहां तक वैश्विक पहुंच और महत्वाकांक्षाओं के साथ अग्रणी एलएसी देश है, स्पष्ट रूप से इस प्रयास में भारत के लिए प्रमुख भागीदार रहा है। इस प्रकार यह खंड मुख्य रूप से वैश्विक शासन में

भारत-ब्राजील की भागीदारी का विश्लेषण करने पर केंद्रित है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सुधार

नए स्थायी सदस्यों को जोडकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का सुधार हाल ही में भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय आम सहमति भी है कि यूएनएससी अपने मौजूदा स्वरूप में वास्तविकताओं को दर्शाता है। ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी ने चार देशों के लिए स्थायी यूएनएससी सदस्यता की मांग करते हुए जी4 समूह का गठन किया है। जी4 , और भारतीय स्थिति के निहितार्थ को लागू करते हुए , कम सामर्थ्य वाली मध्य शक्तियों के 'यूनाइटिंग फॉर कंसिस्टेंस ' समूह द्वारा विरोध किया गया है, जिस समूह में एलएसी के अर्जेंटीना , मैक्सिको, कोलंबिया और कोस्टा रिका शामिल हैं। जी4 के अंतर्गत ब्राज़ील के वाद-विवाद भारत के सबसे करीब हैं। चिली और इक्वाडोर ने भी यूएनएससी में भारतीय सदस्यता को समर्थन देने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है।

भारतीय विदेश नीति का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) , यानी आईएमएफ और विश्व बैंक का लगातार सुधार है , जैसे कि उभरती हुई

अर्थव्यवस्थाओं के लिए उनके पास कई सुझाव है कि उन्हें कैसे चलाया जाता है। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में संरक्षणवाद के बढ़ते चलन का भारत भी विरोध कर रहा है। भारत और ब्राजील द्विपक्षीय रूप से मिलकर काम करते हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ब्रिक्स समूह के एक हिस्से के रूप में काम करते हैं। ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ़ ने 2012 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान आईएफआई में सुधार और 'अंतरराष्ट्रीय संरक्षणवाद' का मुकाबला करने पर जोर दिया था। हालांकि, दो कृषि सब्सिडी के वैश्विक स्तर पर विवादित मुद्दे पर भारत और एलएसी में इस तरह के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर अभिसरण दृष्टिकोण हैं। अपनी ग्रामीण गरीबी के प्रति सचेत, भारत उच्च कृषि आयात शुल्क लेता है। दूसरी ओर , ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे एलएसी कृषि महाशक्तियां कृषि व्यवसाय के लिए वैश्विक बाधाओं में कमी की तलाश कर रही है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसने 2003 में कैनकन बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान अग्रणी विकासशील देशों में भारत और ब्राजील के बीच घनिष्ठ सहयोग को बाधित नहीं किया।

दक्षिण-दक्षिण संस्थान निर्माण

आईएफआई सुधार की धीमी गति से निराश ब्रिक्स विकास बैंक का विचार भारत और एलएसी में जोर पकड़ रहा है। ब्रिक्स रूब्रिक के तहत भारत और ब्राजील के बीच घनिष्ठ सहयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अमेरिकी प्रतिबंधों जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

भारत और ब्राजील तीन में से दो सदस्यों के साथ आईबीएसए त्रिपक्षीय, उभरती शक्तियों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। अपने तीनों सदस्यों द्वारा साझा किए जाने वाले लोकतंत्र के सामान्य राजनीतिक मूल्यों के संदर्भ में आईबीएसए, ब्रिक्स से प्रतिष्ठित है, और यह भी एक तथ्य यह है कि तीनों शक्तियां वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन की उच्च तालिका के सापेक्ष सभी 'बाहरी' हैं। भारत और ब्राजील, दक्षिण की प्रमुख मध्यम शक्तियों के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के निरंतर लोकतंत्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आईबीएसए के संगठनात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लक्ष्य को साझा करते हैं।

आईबीएसए के तत्वावधान में भारत-ब्राजील सहयोग ने पहले ही विकास के कई क्षेत्रों को समाहित किया है तथा संगठन को अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ जोड़ने के प्रस्ताव भी हैं।

उदाहरण के लिए , ब्राजील के विदेश मंत्री सेलसो अमोरिम ने 2007 में अपनी भारत यात्रा के दौरान एक विस्तारित दक्षिण-दक्षिण आर्थिक स्थान बनाने के लिए आईबीएसए, मर्कोसुर और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) के बीच एक संबंध की वकालत की थी। भारत और ब्राजील ने नियमित रूप से निर्धारित आईबीएसए समुद्री अभ्यास के नवीनतम भाग के रूप में भी अपना पहला नौसैनिक ईंधन भरना शुरू किया जिसे आईबीएसएएमएआर का नाम दिया गया। इन अभ्यासों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा आपदा राहत, बंधक बचाव, एंटी-पायरेसी और अन्य समान प्रयासों में पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा देना है।

जलवायु परिवर्तन

वैश्विक पर्यावरण शासन में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के विकास के प्रमुख निहितार्थ हैं, विशेष रूप से भारत और एलएसी देशों जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए। इस बात की गंभीर चिंता है कि कोई

भी जलवायु समझौता दक्षिण में आर्थिक विकास को प्रभावी रूप से सीमित करेगा। भारत और कई एलएसी देश किसी भी भविष्य के जलवायु समझौते की आधारशिला के रूप में 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी ' के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।

जी-8 शिखर सम्मेलन से पहले एक हालिया संयुक्त वक्तव्य में, भारत और ब्राजील ने जलवायु परिवर्तन के लिए 'विकसित दुनिया में सतत उत्पादन और खपत पैटर्न ' पर दोषारोपण किया और कहा कि 'विकासशील देशों में गरीबी का स्थायी समाधान नहीं था '। जलवायु संबंधी वार्ताओं में बेसिक ब्लॉक के सदस्यों के रूप में ब्राजील और भारत एक साथ मिलकर काम करते है , जो कि एक बड़े विकासशील देश की समन्वित आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। नवीकरणीय ऊर्जा को काम मे लाने में एक वैश्विक नेता के रूप में , ब्राज़ील जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भारत की सहायता कर सकता है जैसा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्य योजना में व्यक्त किया गया है।

आतंकवाद और परमाणु हथियार

आतंकवाद जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करने का क्षेत्र, हाल के वर्षों में कोलंबिया और मैक्सिको के अपवाद के साथ, एलएसी देशों के लिए कम प्रासंगिक रहा है। फिर भी , कई एलएसी देशों ने अग्रसक्रिय होकर 2008 के मुंबई हमलों की कड़ी निंदा की। इनमें ब्राजील , अर्जेंटीना, मैक्सिको, कोलंबिया, चिली, वेनेजुएला और अन्य शामिल थे। निंदा और एकजुटता के अपने बयान में कोलंबिया ने अपने खुद के आतंकवाद की चुनौती का भी आह्वान किया। एलएसी राज्यों में, भारत कोलंबिया , मैक्सिको और संभवतः ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन के लिए वार्ता में तेजी लाने के लिए, जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में अनुमेय नहीं है के लिए घनिष्ठता से काम कर सकता है।

भारत और एलएसी (विशेष रूप से ब्राजील और अर्जेंटीना) परमाणु अप्रसार के अंतर्राष्ट्रीय शासन के लिए पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। हालाँकि , 1990 के बाद से उनकी स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। पोखरण-पश्च भारत अब परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के भीतर एक परमाणु हथियार देश के रूप में शामिल करने की मांग करता है। दूसरी ओर, एलएसी राज्यों ने

1994 में ब्राज़ील और अर्जेंटीना के प्रवेश द्वारा लाटेलोको की संधि में परमाणु हथियारों के विरोध को ठोस कर दिया है , जिसने इस क्षेत्र में एक परमाणु हथियार-मुक्त क्षेत्र स्थापित किया है। ब्राजील और अर्जेंटीना ने 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षणों की निंदा की , हालांकि पहले वालों ने कथित तौर पर भारतीय कदम की गुप्त रूप से प्रशंसा की थी। परमाणु मुद्दा हालांकि जल्द ही भारत-एलएसी संबंधों की कार्यसूची से गायब हो गया और यह व्यावहारिकता के आने वाले समय के लिए बने रहने की संभावना है।

संप्रभुता एवं मानवीय हस्तक्षेप

शीत युद्ध के बाद की दुनिया में राजनीतिक दमन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर जनहानि को रोकने के लिए एक देश के भीतर जबरदस्ती हस्तक्षेप पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए सिद्धांत का उदय हुआ है। इस सिद्धांत को रक्षा, या आर2पी के लिए जिम्मेदारी करार दिया गया है , और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर अधिकांश यूरोपीय देशों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और प्रमुख राजनीतिक कारकों द्वारा दृढ़ता से इसे समर्थित किया गया है। हालांकि , आर2पी एक नया

अंतर्राष्ट्रीय मानदंड नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर या अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई उल्लेख नहीं करता है। रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों द्वारा इसका लगातार विरोध किया गया है।

एलएसी देशों को भी आमतौर पर संप्रभुता के विचार के लिए शामिल किया गया है और इसलिए संदेह के साथ आर2पी से उपचारित किया गया है। ये अनसुलझे सवाल हमेशा से रहे हैं कि क्या आर2पी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है , जिसका वास्तविक उद्देश्य धनी पश्चिमी शक्तियों को वैश्विक रूप से दक्षिण में हस्तक्षेप करने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम करना है।

ब्राजील ने हाल ही में एक समझौता फार्मूला का प्रस्ताव किया है, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्टिंग (या आरडब्ल्यूपी) कहा जाता है। यह व्यापक रूप से आर2पी के सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कड़ी शर्तें निर्धारित करता है ताकि अंतःस्थ देशों द्वारा इसके दुरुपयोग

से बचा जा सके। भारत भी पूर्व में आर2पी के अपने विरोध से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। स्पष्ट रूप से , एक तरफ पश्चिमी देशों की स्थिति और दूसरी तरफ रूस और चीन की स्थिति को दरकिनार करने के लिए भारत और ब्राजील के लिए आरडब्ल्यूपी प्रस्ताव पर संयुक्त रूप से काम करने का एक बड़ा अवसर है।

सांस्कृतिक एवं जनता-दर-जनता से संबंध

सटीक शब्दों में, लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभाव सबसे पहले पुर्तगाली उपनिवेशवाद के माध्यम से भारत तक पहुंचे थे। पुर्तगाली रोमन ईसाई धर्म को मालाबार तट, गोवा और मुंबई के पास के क्षेत्र में लाये जिससे केरल, गोवा, मैंगलोर क्षेत्र और महाराष्ट्र में जीवंत ईसाई समुदाय पैदा हुए। पुर्तगाली संपर्क के परिणामस्वरूप भारत में ब्राजील से आम और नारियल लाए गए, जबकि ब्राजील के मैनिओक और काजू ने भारत में प्रवेश किया। *पंचतंत्र* और *हितोपदेश* के स्पेनिश अनुवादों ने लैटिन अमेरिकी विशिष्ट वर्गों के लिए भारत की पहली जागरूकता पैदा की।

भारत और स्पैनिश लैटिन अमेरिका के बीच सबसे पहला ज्ञात संपर्क एक भारतीय गुलाम के रूप में एक हिंदू महिला थी

जिसका नाम मीरा था, जिसका पुर्तगाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसका ईसाई धर्म में धर्म-परिवर्तन करा दिया गया था और अंततः 17 वीं शताब्दी के प्रारंभ में मैक्सिको के शहर पेबला में एक धनी जोड़े को बेच दिया गया था। उसके मालिकों की मृत्यु के बाद   , वह एक कॉन्वेंट में शामिल हो गई और प्यूब्लान के लोगों द्वारा उसकी धर्मपरायणता के लिए उसका अभिनंदन किया गया। मैक्सिको के इतिहास में उसे *ला चाइना पोबलाना* के नाम से जाना जाता है। अपनी जन्मभूमि से पहनी हुई साड़ियों ने उस समय की प्यूब्ला की महिलाओं के बीच पोशाक की एक नई शैली को स्पष्ट रूप से प्रेरित किया।

आधुनिक समय में, 1920 के दशक ने भारतीय और लैटिन अमेरिकी कलाकारों और बुद्धिजीवियों के बीच पहला ठोस लेन-देन देखा था। चिली के कवि पाब्लो नेरुदा ने 1929 में भारत का दौरा किया और रवींद्रनाथ टैगोर ने 1924-25 में तीन महीने साहित्यकार विक्टोरिया ओकैम्पो के अतिथि के रूप में अर्जेंटीना में बिताए, जहाँ उन्होंने अपनी कुछ कविताओं की रचना की।

हालाँकि, लैटिन अमेरिकी लेखक और विचारक जो सबसे घनिष्ठता से भारत से जुड़े हुए थे वे निस्संदेह मैक्सिकन नोबेल पुरस्कार विजेता ऑक्टेवियो पाज थे। 1960 के दशक में भारत में मैक्सिको के राजदूत के रूप में उनके द्वारा बिताए गए छह साल उनके लिए सबसे अधिक उत्पादक रहे थे। उपमहाद्वीप में एक पूरी तरह से नई सभ्यता के साथ उनकी आकर्षक मुठभेड़ का परिणाम उनकी कुछ बेहतरीन कविताओं और निबंधों के रूप में हुआ और उनके जाने के बाद भी भारत का उनकी कविता से प्रभावित होना जारी रहा। हालांकि पाज़ ने हमेशा दावा किया कि भारत के साथ उनका संबंध ज्ञान के बजाय प्यार में निहित था, उनके कृति *इन लाइट ऑफ़ इंडिया*

ने आलोचकों को संस्कृत कविता, बौद्ध तर्क और इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच मुठभेड़ जैसे विविध विषयों पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों से प्रभावित किया।

लैटिन अमेरिकियों के लिए , भारत की छवि धीरे-धीरे आध्यात्मिकता के साथ अधिक मूर्त भूगोल के साथ जुड़ी हुई विदेशी भूमि से योग , फिल्मों, कला, नृत्य और व्यंजनों की उत्पत्ति से विकसित भूमि के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और कल्याण के मार्ग के रूप में योग अब इस क्षेत्र में सर्वव्यापी है। कई हजार लैटिन अमेरिकी साईं बाबा , ब्रह्मकुमारियों और हरे कृष्ण के अनुयायी हैं। शाहरुख खान और आमिर खान जैसे भारतीय अभिनेताओं ने यहाँ लोकप्रियता हासिल की है और हाल ही में एक हिंदी फिल्म में प्रख्यात मैक्सिकन अभिनेत्री बारबरा मोरी ने अभिनय किया है।

भारतीय सरकार ने मैक्सिको सिटी में गुरुदेव टैगोर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जैसी पहल के साथ जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत में पाठ्यक्रम प्रदान करने की व्यवस्था करता, इस क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान

को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। भारत अपने आईटीईसी कार्यक्रम के तहत शैक्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है , जिसके तहत भारत में हर साल लगभग 100 लैटिन अमेरिकी अध्ययन करते हैं, जिसमें व्यावहारिक रूप से सभी खर्चों का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक मैक्सिकन विश्वविद्यालय , एल कोलेजियो डी मेक्सिको का भारत में स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है, जिसे 2010 में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित भारतीय अध्ययन में एक आसन के साथ संपन्न किया गया था। चिली के पूर्व राजदूत जॉर्ज हेइन द्वारा हाल ही में किए गए एक व्यापक कार्य को, ऑक्टेवियो पाज के बाद से लैटिन अमेरिकी दृष्टिकोण से भारत के पहले प्रमुख विश्लेषण के रूप में जाना जाता है।

हाल के वर्षों में, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से संगीत प्रभाव भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में व्याप्त होना प्रारंभ हो गया है। साल्सा, बाचाटा, मेरेंगु और रेगेटन संगीत अब भारतीय महानगरों में नृत्य क्लबों में बजाया जाता है और इसने भारतीय सिनेमा को भी प्रभावित किया है। भारत में कई लैटिन नृत्य स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। इसकी उभरती हुई शैलियों में फ्रांसीसी-कैरेबियाई ज़ौक और कैपीओइरा, ब्राजीलियाई

मार्शल आर्ट प्रारूप शामिल हैं।

भारत में लैटिन अमेरिकी दूतावास, भारत में संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की पहल कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित स्पैनिश दूतावास का सांस्कृतिक केंद्र, इंस्टीट्यूटो सर्वेंट्स, राजधानी में कई लैटिन अमेरिकी फिल्म समारोहों और पाकसाज और स्पेनिश भाषा कक्षाओं की मेजबानी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

सांस्कृतिक संबंधों के बढ़ते जाल ने, भारत में स्पेनिश भाषा सीखने में बढ़ती रुचि को जन्म दिया है। स्पैनिश सिखाने के लिए बड़ी संख्या में निजी भाषा स्कूल अब भारत के प्रमुख शहरों में मौजूद हैं और स्पैनिश भाषा का भारतीयों की पसंद की विदेशी भाषा के रूप में पारंपरिक रूप से लोकप्रिय रही फ्रेंच को जल्द ही प्रतिद्वंदिता देने की संभावना है।

आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ, एलएसी में भारतीय प्रवासी बढ़ने लगे हैं। भारतीय मूल के एलएसी नागरिक बड़ी संख्या में 19वीं सदी से पहले से ही कारीकोम देशों में, 20वीं शताब्दी के मध्य से व्यापारियों के तौर पर पनामा में और हाल ही में ब्राजील के साओ पाओलो जैसे

शहरों में मौजूद है। भारतीय पर्यटक समुद्र तटों और प्राचीन सभ्यताओं से लेकर साल्सा त्योहारों तक हर चीज के लिए लैटिन अमेरिका की यात्राएं करने लगे हैं। आने वाले दशक में दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा और प्रवास के बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है।

आगे की राह

इस प्रकार भारत-एलएसी संबंधों पर काफी हद तक आर्थिक कारक हावी रहें हैं। आर्थिक अवसर का विस्तार करने और व्यापार एवं निवेश को प्रगाढ़ करना, जिसकी संभाव्यता का अहसास किया जाना अभी शेष है, वह दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह आर्थिक रूप से ठप पश्चिम और दक्षिण-दक्षिण संबंधों को गहरा करने के समय में भी अधिक महत्व रखता है। इसे हासिल करने के लिए व्यवसायों के विस्तार के लिए मजबूत व्यवस्था सुविधा, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट एजेंसियों को उन्नत करने व पूर्णरूपेण उपयोग किये जाने, सीधी हवाई सेवाओं को स्थापित करने (संभवतः दक्षिण अफ्रीका को एक केंद्र के रूप में स्थापित कर) तथा स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा प्रशिक्षण को भारत में विस्तार करने हेतु

क्रेडिट लाइनों की आवश्यकता होगी।

हालांकि, यह राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों के क्षेत्र में है जहां संबंधों से अदायगी वास्तव में क्रांतिकारी हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से ब्राजील जैसे बड़े लैटिन अमेरिकी देशों में विदेश नीति के लक्ष्य भारत के समान ही हैं जैसे कि - आर्थिक विकास और मानव विकास के लिए अपने स्थान को संरक्षित करने की इच्छा और अन्य चीजों के साथ, प्रमुख प्रभाव वाले अभिनेताओं के रूप में वैश्विक मंच पर उभरने की इच्छा , आईएमएफ और विश्व बैंक में विस्तारित भूमिका , यूएनएससी में एक मजबूत आवाज, और वैश्विक मानदंड स्थापित करने में अग्रणी रहना। उदाहरणार्थ ब्राजीली विदेश नीति 'युद्धाभ्यास के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए और अपनी सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का सबसे बड़ा संभव विविधीकरण ' करते हुए अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है। भारत ने भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है। वैश्विक शासन का प्रजातंत्रीकरण एक मुख्य आम लक्ष्य है। दक्षिण-दक्षिण संबंधों को सक्रिय और मजबूत करना , जिनमें से भारत-एलएसी संबंध

एक प्रमुख भाग है, इस तरह की रणनीति की आधारशिला है।

ऊर्जा सुरक्षा भारत की अत्यावश्यकता है जिसमें एलएसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तेजी से अस्थिर पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के साथ, एलएसी हाल के वर्षों में नयी तेल और गैस की खोजों के साथ दुनिया के कुछ ही भागों में से एक है। अर्थव्यवस्था और सशस्त्र बलों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में ऊर्जा, विशुद्ध रूप से आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यताओं के बीच अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है। गारंटीकृत उत्पादन के साथ ऊर्जा अधिग्रहण के साथ इक्विटी अधिग्रहण का विस्तार-क्षेत्र के प्रति भारतीय नीति के लिए साझा लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ना एक साझी जागरूकता भी है कि आर्थिक विकास के जीवाश्म ईंधन के नेतृत्व वाला मॉडल केवल कुछ ही दशक और चल सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के एक नए प्रतिमान को नया रूप देने, शून्य-अपशिष्ट विकास पर ध्यान केंद्रित करना भारत और एलएसी देशों दोनों के राष्ट्रीय हितों में है और इस तरह की बायोइंडस्ट्रीज़ का विकास सहयोग के लिए एक एजेंडा आइटम होना चाहिए।

एलएसी एकीकरण की प्रक्रिया भारतीय नीति के संभावित प्रमुख प्रभावों के साथ एक विकास है , हालांकि अभी भी यह अनिश्चितताएं बनी हुई हैं कि यह प्रक्रिया कितनी दूर तक जाएगी। एलएसी नेताओं ने महसूस किया है कि एकीकरण उनके व्यक्तिगत और सामूहिक वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अगले दशक में आर्थिक एकीकरण संभवत: इस क्षेत्र में प्रमुख केंद्रबिंदु रहेगा। हालाँकि , एलएसी विदेश नीति प्राथमिकताओं का एक अभिसरण , जैसा कि हाल ही में होंडुरास और परागुयन संकट के दौरान देखा गया था यह और भी कम अंतराल पर बार-बार हो सकता है। एक तर्कपूर्ण बहस है कि लोकतंत्र का विचार , यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वयं न हों तो, लैटिन अमेरिका में मर्कासुर जैसी पहलों की सफलता में एक प्रमुख प्रस्तावक हैं। मर्कासुर जैसे आर्किटेक्चर दक्षिण एशियाई एकीकरण की परियोजना के लिए खुले टेम्पलेट्स के रूप में कार्य कर सकते हैं जो वर्तमान में बमुश्किल नवजात अवस्था में है। नई दिल्ली को इस क्षेत्रीय गतिशीलता पर कड़ी निगरानी रखने से लाभ होगा

भारत और एलएसी को जोड़ने में साझा प्रजातात्रिक मानदंड

दूसरे महत्वपूर्ण संपत्ति है। इनके प्रजातांत्रिक प्रत्यय-पत्र दोनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक विश्वसनीय आवाज प्रदान करते हैं। इस आवाज का इस्तेमाल मानव अधिकारों को बढ़ाने और नरसंहार को रोकने के लिए किया जाना चाहिए लेकिन साथ ही इनका उपयोग उत्तर में प्रमुख शक्तियों द्वारा आर2पी जैसे विवादास्पद नए प्रस्तावों के दुरुपयोग को भी सीमित करता है।

अंतिम लेकिन न्यूनतम नहीं , भारत और एलएसी देश कई समान आंतरिक विकासात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं। इनमें उच्च आय असमानता, नस्लीय/जातीय बहिष्कार, कमजोर और अराजक शहरी शासन , और खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अलग करने और बड़े पैमाने पर करने के लिए तुलनात्मक कार्य में संलग्न होकर एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। यद्यपि इस लेख के क्षेत्र ने इन क्षेत्रों के गहन उपचार की अनुमति प्रदान नहीं की है, लेकिन संयुक्त भारत-एलएसी एजेंडा में उनका समावेश महत्वपूर्ण है।

1 N.P. Chaudhary, India's Relations with Latin America, New Delhi: South Asian Publishers, 1990, p. 12.

2 Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History, New Delhi: Penguin, 2004.

3 N.P. Chaudhary (1990), p. 9.

4 N.P. Chaudhary (1990), p. 9.

5 N.P. Chaudhary (1990), p. 18.

6 N.P. Chaudhary (1990), pp. 23-24.

7 N.P. Chaudhary (1990), pp. 24-25.

8 N.P. Chaudhary (1990), pp. 28-49.

9 These were as follows - Argentina and Colombia during the Junagadh, Hyderabad, and Kashmir debates in 1948; Ecuador, Cuba in the Kashmir debate in 1950; Chile, Ecuador during the Goa debate in 1961.

10 A full account of the debates and positions of various LAC states in the USSC is provided in N.P. Chaudhary (1990), pp. 139-156.

11 Ravi Kumar, 2010

12 Indian Ministry of Commerce, Focus:LAC Programme, 2011, see http://commerce.nic.in/trade/international_tpp_lac.pdf, accessed on November 4, 2012.

13 Deepak Bhojwani, "India's Prospects in Latin America and the Caribbean," Indian Foreign Affairs Journal, vol. 7, no. 4, October-December 2012, pp. 433-445.

14 Deepak Bhojwani, "India's Prospects in Latin

America and the
Caribbean," 2012.

15 Deepak Bhojwani, "India's Prospects in Latin America and the Caribbean," 2012.

16 "Latin America as an FDI Hotspot," Economist Intelligence Unit, 2012.

17 'India, Brazil could learn from each other: Krishna,'The Hindu, August 31, 2009, available at http://www.thehindu.com/news/article12709.ece, accessed on October 30, 2012

18 'PVR vs Cinepolis: The Show (Down) Is On,' Forbes India, April 30, 2012, available at http://forbesindia.com/article/boardroom/pvr-vs-cinepolis-the-show-down-is-on/32838/1#ixzz2Ar1fqZHz, accessed on October 31, 2012

19 "The Emergence of Latin Multinationals," Organization for Economic Cooperation and Development, 2007.

20 "WorldBank:South-

Southinvestmentboom,"FinancialTimes,January 13, 2011, available at http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/01/13/world-bank-south-south-investment-boom/#axzz2At9ca2o8, accessed on November 1, 2012.

21 "World Bank: South-South investment boom," 2011

22 Mercosur is a customs union and common market consisting of Brazil, Argentina, Uruguay, and Venezuela as full members. Paraguay's membership was suspended in 2012 after the questionable impeachment of its president Fernando Lugo.

23 Government of India, Ministry of Commerce and Industry, see http:// commerce.nic.in/trade/international_ta_indchile.asp, accessed on October 31, 2012.

24 Indian Ministry of Commerce, Focus:LAC programme.

25 see http://newsletters.cii.in/newsletters/mailer/LAC_Newsletter/ August10/Media/IPF_online.pdf, accessed November 4, 2012.

26 Amitava Tripathi, 'India-Brazil Strategic Engagement: Vistas for Trade, Commerce and Investment Interchange Possibilities for the Future,' ICWA Commentary, Indian Council of

World Affairs, New Delhi, July 2012.

27 ‘India to diversify energy sourcing,’ Hindustan Times, October 25, 2012, available at http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/India-to-diversify-energy-sourcing/Article1-949645.aspx, accessed on November 4, 2012.

28 Deepak Bhojwani, ‘Latin America - Energising India,’ June 2012,
Indian Council of World Affairs, New Delhi.

29 Deepak Bhojwani, June 2012.

30 “India, Brazil to tie up for bioenergy,” Times of India, May 1, 2012, available at http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-05-01/ vadodara/31526310_1_cent-ethanol-india-and-brazil-oil-imports, accessed on November 20, 2012.

31 Deepak Bhojwani, “Latin America - Energising India,” 2012.

32 “Monnet Ispat in talks for coal mine buy in Colombia,” Business Standard, November 20, 2012, http://business-standard.com/india/

news/monnet-ispat-in-talks-for-coal-mine-buy-in-colombia/493062/

33 “Essar buys $1.2bn Ecopetrol crude,” Financial Times, August 16, 2012, available at http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/08/16/essar-buys-1-2bn-ecopetrol-crude/#axzz2DLsrecxy

34 Deepak Bhojwani, “Latin America - Energising India,” 2012.

35 “Reliance teams up with China’s CNPC to win oil block in Peru,”

Rediff, September 18, 2008, available at http://www.rediff.com/ money/2008/sep/18reliance2.htm

36 "India's Oct LNG imports edge up from Sep, jump 24% on year to 1.24 mil mt," Platts, November 5, 2012, available at http://www. platts.com/RSSFeedDetailedNews/RSSFeed/NaturalGas/7223058, accessed on November 20, 2012.

37 "India: Latin America's next big thing?" Inter-American Development Bank, 2010, p. 77

38 "India and Latin America and the Caribbean: Opportunities and challengesintradeandinvestment relations," United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2011, p. 49

39 'Statoil, Petrobras quit ONGC gas field,' Indian Express, April 2, 2010, available at http://www.indianexpress.com/news/statoil-

petrobras- quit-ongc-gas-field/599184, accessed on November 20, 2012.

40 "India and Latin America and the Caribbean ," ECLAC, 2011, pp.
48.

41 "India and Latin America and the Caribbean ," ECLAC, 2011, pp.
48.

42 "Jindal Steel sets Aug 10 deadline for Bolivian govt to resolve issues," TheHindu,July15,2012,availableathttp://www.thehi ndubusinessline.
com/companies/article3642528.ece

43 "Why Jindal Steel exited its $2.1 bn venture in Bolivia," Rediff, August 15, 2012, available at http://www.rediff.com/business/slide- show/slide-show-1-special-why-jindal-steel-exited-its-uad-2-point-1- bn-venture-in-bolivia/20120815.htm

44 Rajiv Bhatia, "Celebrating an old relationship," Daily Pioneer,
November 17, 2010.

45 "India and Latin America and the Caribbean ,"

ECLAC, 2011, pp. 42

46 "India and Latin America and the Caribbean ," ECLAC, 2011, pp. 48

47 'What Renuka Sugars learnt from Brazil,' Forbes India, October 31, 2012, available at http://forbesindia.com/article/cross-border/what-renuka-sugars-learnt-from-brazil/34009/2, accessed on December 1, 2012.

48 "India and Latin America and the Caribbean ," ECLAC, 2011, pp. 49.

49 Amitava Tripathi, 'India-Brazil Strategic Engagement'.

50 Sumati Varma, "India and Latin America: An emergent investment story of the pharmaceutical industry," FPRC Journal, Foreign Policy Research Center, Vol. 3, 2012.

51 'India, Brazil to protest at WTO against Dutch medicine seizure,' Press Trust of India, January 31, 2009.

52 'Foraying into Latin America,' Economist Intelligence Unit, May 24, 2012.

53 'Driving into the future: an exports perspective,' EEPC India, 2009

54 "India: Latin America's next big thing?", 2010, p. 77

55 'Godrej Consumer Products acquires 60% stake in Chilean firm,' Business Standard, January 23, 2012, available at http://www.business-standard.com/india/news/godrej-consumer-products-acquires-60- stake-in-chilean-firm/155998/on, accessed on November 29, 2012

56 “India: Latin America’s next big thing?”, 2010, p. 79

57 ‘India, Brazil to forge stronger ties to achieve $10 billion bilateral trade,’ The Hindu, March 9, 2011.

58 Deepak Bhojwani, “Latin America - Energising India,” 2012.

59 Deepak Bhojwani, “Latin America - Energising India,” 2012.

60 “India: Latin America’s next big thing?”, 2010, p. 116

61 “India: Latin America’s next big thing?”, 2010, p. 129

62 “India: Latin America’s next big thing?”, 2010, p. 105

63 “India and Latin America and the Caribbean ,” ECLAC, 2011, p. 51

64 Jorge Heine in ‘Debate - Latin America and the Caribbean: the next step for India,’ Indian Foreign Affairs Journal, v. 6, no. 1, January-March 2011, pp. 1-27

65 Jorge Heine, “Debate - Latin America and the

Caribbean," 2011.

66 Amitava Tripathi, 'India-Brazil Strategic Engagement: Vistas for Trade, Commerce and Investment Interchange Possibilities for the Future,' ICWA Commentary, Indian Council of World Affairs, New Delhi, July 2012.

67 Luis Inacio Lula da Silva, 'Consolidation of the India-Brazil strategic partnership,' The Hindu, June 3, 2007.

68 Oliver Stuenkel, 'Seeing India through Brazilian eyes,' Seminar,
February, 2012. Also see by the same author "The case for stronger

Brazil-India relations," Indian Foreign Affairs Journal, vol. 5, no. 3, July-September 2010, pp. 290-304.

69 'India, Brazil could lead the way in the bioindustries model - Interview with Dr. Carlos Nobre, climate scientist,' The Hindu, December 11, 2010.

70 "Mexico can be India's entry point into Latin America,: Interview with Vicente Fox," Businessworld, October 15, 2012, available at http:// www.businessworld.in/en/storypage/-/bw/mexico-can-be-india-s- entry-point-to-latin-america/574793.0/page/0, accessed on December 18, 2012.

71 "India, Mexico sign extradition treaty," PTI, September 10, 2007.

72 Rajiv Bhatia, "Celebrating an old relationship," The Pioneer,
November 17, 2010.

73 Rajiv Bhatia, "Celebrating an old relationship," 2010.

74 "India-Mexico trade to touch $10 bn by 2015,"

IANS, November 1, 2012.

75 R. Viswanathan, “Argentina – emerging as a long term economic partner of India in Latin America,’ Indo-lac Business Magazine, March 2009.

76 R. Viswanathan, “Argentina – emerging as a long term economic partner of India in Latin America,” 2009.

77 “Argentina seeks Indian support in territorial claim,” The Hindu, February 24, 2012.

78 ‘Indian oil and gas company desists from Falklands’ exploration partnership,’ Mercopress, May 16, 2012, available at http://en.mercopress.com/2012/05/16/indian-oil-and-gas-company-desists- from-falklands-exploration-partnership, accessed on December 19, 2012.

79 Deepak Bhojwani, “India’s prospects in Latin America,” 2012.

80 “India-Chile relations,” ICWA Paper, Indian Council for World

Affairs, New Delhi, 2012.

81 Vivek Katju in 'Debate - Latin America and the Caribbean: the next step for India,' Indian Foreign Affairs Journal, v. 6, no. 1, January-March 2011, pp. 1-27

82 Matthew Clark, "Latin America's surprise rising economic star:

Peru," Christian Science Monitor, January 5, 2010, available at http:// www.csmonitor.com/World/Americas/2010/0105/Latin-America-s- surprise-rising-economic-star-Peru, accessed on December 22, 2012.

83 for example, Guyanese president Bharrat Jagdeo visited India in 2003 and 2004, and President Ronaldo Ronald Venetiaan of Suriname in 2003.

84 The Organization of American States (OAS) spans the entire region but also includes the United States and Canada. Politically, the OAS is rooted in the US-led anti-communist front, whereas CELAC represents an attempt at regionalism independent of Washington's shadow. The post-Cold War period has given a major impetus to regionalism in the LAC, of which the founding of CELAC is only the latest example.

85 See http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/20306/Joint +Statement+on+the+First+IndiaCELAC+Troika+For

eign+Ministers
+Meeting, accessed December 15, 2012.

86 John Cherian, "South Meets South," Frontline, vol. 29, No. 17, August 25, 2012, available at http://www.frontlineonnet.com/fl2917/ stories/20120907291705200.htm, accessed on December 15, 2012.

87 "Paraguay suspended from Mercosur citing Ushuaia Protocol on Democratic Committment," Pressenza, June 29, 2012, available at http://www.pressenza.com/2012/07/paraguay-suspended-from- mercosur-citing-ushuaia-protocol-on-democratic-committment/ , accessed on December 26, 2012.

88 Deepak Bhojwani, "India's Prospects in Latin America and the
Caribbean," 2012.

89 Vivek Katju in 'Debate - Latin America and the Caribbean: the next step for India,' Indian Foreign Affairs Journal, v. 6, no. 1, January-March 2011, pp. 1-27

90 "India, Brazil said signed framework accord to

cooperate in field of
outer space," The Hindu, January 26, 2004.

91 "India, Brazil, South Africa to develop satellites jointly," AFP, April
16, 2010.

92 "Brazil urges Indian govt to provide training to scientists for space
programs," Political and Defense Weekly, September 15, 2012.

93 Deepak Bhojwani, "India's prospects in Latin America," 2012.

94 "India gets first Embraer jet with Indian airborne radar tech," The Hindu, August 17, 2012, available at http://www.thehindubusinessline. com/industry-and-economy/logistics/article3785186.ece, accessed on December 1, 2012.

95 R. Swaminathan, "Brazil asks India to provide inputs on MMRCA selection," Political and Defense Weekly, March 6, 2012.

96 "India to share Rafale documentation with Brazil," InfoRel, February 20, 2012.

97 "India to share Rafale documentation with Brazil," 2012.

98 "Brazil urges Indian govt to provide training to scientists for space programs," Political and Defense Weekly, September 15, 2012.

99 "India Ecuador to explore technology transfer," PTI, July 19, 2008.

100 "India, Chile sign four pacts," The Hindu, April

22, 2008.

101 Deepak Bhojwani, "Prospects for India in Latin America and the Caribbean," 2012.

102 Additionally, China and the African Union have been reluctant to endorse the G4 proposal.

103 Oliver Stuenkel, "Leading the disenfranchised or joining the establishment? India, Brazil, and the UN Security Council," Carta Internacional,vol. 5, no. 1, March 2010, University of Sao Paolo.

104 "The case for IMF quota reform," Council for Foreign Relations, October 11, 2012, available at http://www.cfr.org/imf/case-imf-quota-reform/p29248, accessed on January 2, 2013.

105 "BRICS support for IMF rescue plan," Political and Defense Weekly, July 3, 2012.

106 "Trade between Brazil and India should reach $15 billion by 2015," Agencia Brasil, April 1, 2012.

107 Oliver Stuenkel, "The case for stronger Brazil-

India relations," 2010,
pp. 290-304.

108 "Working towards BRICS cooperation, consultation and coordination," Observer research Foundation, available at http://www.observerindia.
com/cms/sites/orfonline/modules/report/ReportDetail.html?cmaid=3 9768&mmacmaid=39769, accessed on January 3, 2013.

109 Akshay Mathur and Neelam Deo, "Brics "hostage" to west over Iran sanctions, need financial institutions," Financial Times, June 27, 2012,

available at http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/06/27/guest-post- brics-hostage-to-west-over-iran-sanctions-need-their-own-financial-institutions/#axzz2HAxatoOz, accessed on January 3, 2013.

110 Siddharth Varadarajan, "Forget the G8, it's time for a BRICS summit," The Hindu, June 8, 2007.

111 See www.ibsa-trilateral.org

112 Oliver Stuenkel, "Why IBSA and BRICS should not merge," FPRC Journal, Foreign Policy Research Center, Vol. 3, 2012.

113 Chris Walden and Marco Vieira, "The New Diplomacy of the South: South Africa, Brazil, India and Trilateralism," Third World Quarterly, vol. 26, no. 5, pp. 1077-1095, 2005

114 "Brazil for IBSA link to Mercosur, SACU," The Hindu, July 17, 2007.

115 Dean Wingrin, "IBSA maritime exercise ends on dramatic note," Defenceweb,

October 29, 2012, available at http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=28281:ibsamar-naval-exercise-ends-on-dramatic-note&catid=51:Sea&Itemid=106, accessed on January 5, 2013.

116 "India, Brazil consolidate strategic ties," The Hindu, June 5, 2007.

117 "Brazil stands by India on climate change stance," Times of India, November 25, 2011, available at http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-11-25/global-warming/30440216_1_climate-change- second-commitment-period-kyoto-protocol, accessed on January 4, 2013.

118 The BASIC bloc of states comprises of Brazil, South Africa, India and China.

119 See http://pmindia.gov.in/climate_change.php

120 Argentina also suffered major terrorist attacks in 1992 and 1994.

121 See http://www.un.org/law/terrorism/index.html.

122 Oliver Stuenkel, "Seeing India through Brazilian

eyes," 2012.

123 Arguably it directly contravenes Article 2(4) of the UN charter.

124 see http://www.un.int/brazil/speech/Concept-Paper-%20RwP.pdf

125 Oliver Stuenkel, "Seeing India through Brazilian eyes," 2012.

126 Octavio Paz, In Light of India, p. 83, New York: Harcourt Brace & Co, 1995.

127 Octavio Paz, In Light of India, 1995, p. 33.

128 Tracy Lopez, “Bollywood comes to Latin America,” Fox News Latino, January 26, 2012, available at http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2012/01/26/bollywood-makes-it-way-to-latin-america/, accessed on January 12, 2013.

129 named the Octavio Paz Chair in Indian Studies. See “India-Mexico Relations,” ICWA, 2012.

130 Jorge Heine, “La Nueva India”

131 for example, at Shiro in Mumbai - see http://shiro.co.in/.

132 for example, Salsa India - see http://www.salsa-india.com/.

133 see http://nuevadelhi.cervantes.es/en/instituto_cervantes_in_india. htm

134 for example, Academia Espanol - see http://www.academiaespanol. com/.

135 particularly in the Colon free trade zone.

136 The exception is the relationship with Brazil, in

which political and
strategic factors have also begun to play a major role.

137 Luiz Alberto Moniz Bandeira, “Brazil as a regional power and its relations with the United States,” Latin American Perspectives, vol. 33, no. 3, May 2006, pp. 12-27.

138 Gian Luca Gardini, The Origins of Mercosur: Democracy and regionalization in South America, New York: Palgrave Macmillan, 2010. Also see Jorge Heine, “Regional integration and political cooperation in Latin America,” Latin American Research review, vol. 47, no. 3, 2012.

अभिस्वीकृति

लेखक भूतपूर्व भारतीय राजदूत दीपक भोजवानी का इस कार्य में उनके द्वारा दी गई मूल्यवान जानकारियों के लिए अभिनंदन करता है। डॉ. ओलीवर स्टंकेल एवं मैरी लोबो को भी धन्यवाद देता है।

सारंग शिडोर लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया पर विशेष फोकस के साथ एक शोधकर्ता और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा, रणनीतिक भविष्यों और भारतीय संबंधों के क्षेत्र में परामर्श दाता है। इनकी पृष्ठभूमि में निजी क्षेत्र में 14 वर्षों का अनुभव, थिंक-टैंक और शैक्षणिक संस्थान का अनुभव शामिल है। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि और इंजीनियरिंग में दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ हैं। उन्होंने कई बार लैटिन अमेरिका का दौरा किया है और स्पेनिश भाषा में कुशल हैं। उनसे sarang.global@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

a

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़,
नई दिल्ली-110001

ISBN 978-93-83445-00-4
9 789383 445004